● वर्ष-2

● अंक-252

रायपुर, मंगलवार
13 जून 2023

● पृष्ठ-6

● मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

इन दिनों — सुभाष चंद्र

अतिक्रमण की भेंट चढ़ी पैदल यात्रियों की जगह

हमारी सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए जगह नहीं है। पैदल यात्री उपेक्षित और जोखिम भरे सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। वाहनों की भीड़-भाड़ के बीच उन्हें अपनी सूझ-बूझ से खतरे उठाते हुए सड़क पार करना पड़ता है। ऐसे में बच्चों और वृद्धों की स्थिति बहुत मुश्किल भरी होती है। महानगरों में हम केवल पैदल पार-पथ पट्टी का रंग-रोगन करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। लेकिन उन पर चलने का अधिकार पैदल यात्रियों को मिले, यह सुनिश्चित नहीं करते। दुनिया भर में पैदल यात्रियों को सड़क पर चलने की बेहतर सुविधाओं के साथ-साथ सड़क पार करने की समुचित प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हर जगह पैदल पार-पथ बने हैं। पैदल यात्रियों के लिए ट्रैफिक लाइटें लगी हैं, जिनका शत-प्रतिशत पालन किया जाता है। जहां ट्रैफिक लाइटें नहीं लगी हैं, वहां वाहन चालक पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार कराते हैं, फिर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। हमें इस संस्कृति को अमल में लाने की आवश्यकता है। पैदल यात्रियों को सड़कों पर होने वाली मुश्किलों पर पहली बार एक समग्र अध्ययन, मई, 2023 में सातवें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह (15-21 मई, 2023) के दौरान देखने को मिला, जिसमें जर्मनी की एक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कंपनी ने एक शोध-पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि हिंदुस्तान की सड़कों पर मारे जाने वाले हर दस लोगों में से एक पैदल यात्री होता है। प्रतिदिन नब्बे पैदल यात्री कभी घर नहीं पहुंच पाते हैं और 165 घायल होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। वर्ष 2021 में दिल्ली में 504, चेन्नई में 297, मुंबई में 174, बंगलूरू में 160, अहमदाबाद में 161, गुरुग्राम में 118, हैदराबाद में 94 और कोलकाता में 78 पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई। कार या हल्के वाहनों ने लगभग अस्सी प्रतिशत पैदल यात्रियों की जान लीं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2021 में कुल 18,900 पैदल यात्री सड़कों पर मारे गए। भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर पैदल यात्रियों के सड़क पार करने की समुचित व्यवस्था न होने से ही ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। इससे निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं? सड़कों की डिजाइन और निर्माण, विभिन्न विभागों यथा लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका, जल और विद्युत विभाग के बीच तालमेल से किया जाना चाहिए। सड़क डिजाइन और जन सुरक्षा की वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए इन सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सड़कों को बार-बार खोदना न पड़े, इसके लिए दोनों ओर जालीदार छत से ढंके, गहरे नाले बनाए जाने चाहिए, जिनमें से हर प्रकार की पाइप लाइनें गुजारी जा सकें और उनकी मरम्मत की जा सके। आवागमन में बाधा डालने वाले हर अवरोध से निदान के बारे में कार्यदायी संस्था का उत्तरदायित्व तय होना चाहिए। फुटपाथ और सड़क निर्माण का काम ठेकेदारों या मजदूरों की मनमर्जी से नहीं, बल्कि जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में सड़क के दोनों ओर बिना फुटपाथ के सड़कों का निर्माण नहीं होना चाहिए। पैदल यात्रियों की संख्या का अध्ययन और उनके अनुपात में फुटपाथों की चौड़ाई निर्धारित होनी चाहिए।

बदली रणनीति, मायावती का मिशन ग्राउंड

चार दशक पुराने कांशीराम मॉडल पर लौट रही बहुजन समाज पाटी

आशीष तिवारी

लगातार चुनावों में हार का मुंह देख रही बहुजन समाज पार्टी ने आखिरकार चार दशक पुराने कांशीराम मॉडल को अपनाकर लोकसभा के चुनाव में जाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके चलते बहुजन समाज पार्टी के रणनीतिकारों ने मायावती को ग्राउंड पर उतारने के लिए मिशन ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया। योजना के मुताबिक मायावती अगस्त के बाद शुरू होने वाले बसपा के कैडर कैंप में अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से न सिर्फ मुखातिब होंगी, बल्कि उनको आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए नए दिशा निर्देश भी देंगी। लंबे समय से बसपा में मांग उठती रही है कि मायावती अगर जमीन पर उतर कर कार्यकर्ताओं से सीधे मुखातिब हों, तो संभव है पार्टी का वोट बैंक भी बढ़े और पार्टी की राजनीतिक हिस्सेदारी भी।

गिरते ग्राफ को संभालने के लिए फिर कांशीराम मॉडल

2007 के विधानसभा चुनावों में बंपर सफलता पाने के बाद मायावती ने 5 साल उत्तर प्रदेश में शासन किया। लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, तो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ इस कदर गिरा कि कभी अपने बलबूते उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली बसपा का इस वक्त महज एक विधायक सदन में मौजूद है। राजनैतिक विश्लेषक रमाकांत चौधरी कहते हैं कि 2012 के बाद गिरते हुए ग्राफ को संभालना मायावती और उनकी पार्टी के लिए न सिर्फ मुश्किल हुआ, बल्कि हालात भी पार्टी के लिए बदतर होते चले गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में तो बसपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई। चौधरी कहते हैं कि बसपा की वर्तमान दशा का जिम्मेदार पार्टी का नेतृत्व ही है। यही वजह है कि बसपा ने अपने गिरते हुए इस जनाधार को संभालने के लिए कांशीराम के उस मॉडल को लाने की योजना बनाई है, जिसकी करीब चार दशक पहले उन्होंने शुरुआत की थी। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक उनकी पार्टी लोगों के घर तक पहुंचने की योजना बना रही है। इसमें मायावती से लेकर पार्टी के कोऑर्डिनेटर और पार्टी के पदाधिकारियों को जन अभियान में शिरकत करने के लिए उतारा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि कांशीराम में अपने आंदोलन के दौरान पैदल चलकर लोगों के घर-घर दस्तक दी थी, उसके बाद ही मिशन के तहत पार्टी का जनाधार तैयार हुआ था।

कांशीराम अपने कैडर के लोगों से रखते थे करीबी

राजनीतिक जानकार रमाकांत चौधरी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में मायावती ही नहीं, बल्कि कांशीराम के दौर से चुनावों में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए कैडर कैंप की महत्वपूर्ण भूमिका होती रही है। यही वजह है कि अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए नई रणनीति के तौर पर कांशीराम मॉडल को बहुजन समाज पार्टी आगे ला रही है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में शामिल एक नेता बताते हैं कि मायावती आने वाले लोकसभा के चुनावों में अपने खोए हुए जनाधार को पाने के लिए कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर मुलाकात करेंगी। राजनीतिक विश्लेषक जनार्दन शुक्ला कहते हैं कि दरअसल बीते कुछ चुनावों में मायावती सिर्फ एक-दो बड़ी रैलियों के माध्यम से ही जनता से मुखातिब होती रही हैं। विपक्षी दलों के नेता लगातार लोगों के घर जाकर न सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करते हैं, बल्कि रात्रि विश्राम का भी आयोजन किया जाता रहा है। ऐसी नई रणनीति में बहुजन समाज पार्टी न सिर्फ पिछड़ी है, बल्कि अपना कोर वोट बैंक का जनाधार भी खोती जा रही है। यही वजह है कि मायावती अब अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जनता से सीधे संवाद करने की काशीराम की तरह की योजना बना रही हैं।

अगस्त से शुरू होगा मायावती का मिशन ग्राउंड

बहुजन समाज पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक अगले कुछ महीनों में उनकी पार्टी बूथ स्तर पर अपनी कमेटियों का गठन कर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करेगी। इन कमेटियों के गठन के बाद पार्टी कैडर कैंप की शुरुआत करेगी। इस कैडर कैंप में बहुजन समाज पार्टी में बहुत ही सधी हुई रणनीति के तहत बूथ स्तर तक के अपने पार्टी पदाधिकारियों को शामिल करने की योजना बनाई है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इन कैडर कैंप में मायावती की शिरकत कराए जाने की पूरी तैयारी चल रही है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अगस्त में शुरू होने वाले इन कैडर कैंप में मायावती कई जिलों के कैंप में शामिल होंगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीते कई चुनावों के दौरान यह पहला मौका होगा, जब मायावती ऐसे आयोजनों में अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव में उनको राजनीतिक दांव पेंच के बारे में जानकारी देंगी।

बसपा में कोई दूसरा मजबूत चेहरा नहीं

दरअसल बसपा को अपनी पूरी रणनीति सिर्फ इसीलिए बदलनी पड़ रही है, क्योंकि इस वक्त उनके पास कोई भी दूसरा बड़ा चेहरा पार्टी में नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जो चेहरे हैं भी वे कांशीराम या मायावती की तरह जनता में उतने जाने पहचाने नहीं हैं कि उनके नाम पर वोट गिरता रहे। यही वजह है कि इस लोकसभा चुनाव में मायावती को अपने चेहरे के साथ ही जनता के बीच कैडर कैंप में जाने की व्यापक रणनीति बनानी पड़ी। बसपा से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मायावती के सिवाय उनके पास पार्टी में चेहरे नहीं हैं। उनका तर्क है कि उनकी पार्टी काफी समय से सत्ता में नहीं है और विपक्ष में होने के चलते उनके नेताओं को अन्य जनसामान्य में इतनी जगह नहीं मिल पाती है। वह कहते हैं कि अपने कैडर और मिशन से जुड़े लोगों के बीच उनकी पार्टी के प्रत्येक बड़े नेता की अपनी एक अलग पहचान है। इसी बलबूते लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है।

चार जुलाई को होगा डब्ल्यूएफआई का चुनाव

नयी दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ ने सोमवार को घोषणा की कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) के चुनाव 4 जुलाई को होंगे। चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) महेश मित्तल कुमार होंगे। आईओए ने न्यायमूर्ति मित्तल कुमार को लिखे अपने पत्र में कहा कि ढ्ढह्र को ङ्ख्नस्नढ्ढ की कार्यकारी समिति के चुनाव कराने के लिए आगे कदम उठाना है, और हम आपको ङ्ख्नस्नढ्ढ के चुनाव कराने के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करके प्रसन्न हैं। चुनाव कराने में सहायता के लिए एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने पर विचार किया है। 4 जुलाई को बुलाई गई डब्ल्यूएफआई की एसजीएम में चुनाव कराने की आवश्यकता है और चुनाव का कार्यक्रम उसी के अनुसार तैयार करना होगा। हम आपकी स्वीकृति की पुष्टि और 4 जुलाई को डब्ल्यूएफआई के चुनावों के

सुचारू संचालन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत के शीर्ष पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने इस साल मार्च में तीन कार्यकाल (12 वर्ष) पूरे किए। खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई के 7 मई के पहले के चुनाव की तारीख को अमान्य और शून्य घोषित कर दिया। इसने संगठन को चलाने और 45 दिनों के भीतर नए सिरे से चुनाव कराने के लिए दो सदस्यीय तदर्थ समिति नियुक्त की।

केंद्र समाधान के लिए पहलवानों से कर रहा बातः खट्टर

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को कहा कि केंद्र उन पहलवानों से बात कर रहा है, जिन्होंने डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन आरोपों के बीच 14 जून को रायव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन पहले बातचीत होनी चाहिए। इससे पहले आज महापंचायत को संबोधित करते हुए बजरंग पुनिया ने कहा कि पहलवानों ने अपना आंदोलन 15 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है और अगर उस समय तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो उनके अगले कदम की घोषणा की जाएगी।खाप नेताओं द्वारा पूर्व ङ्ख्नस्नढ्ढ प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 14 जून के हरियाणा बंद के आह्वान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कुछ लोग राजनीति के लिए ऐसे विषय उठाते हैं। केंद्र सरकार उनसे(पहलवानों से) बातचीत कर रही है। बंद का आह्वान किया गया है लेकिन पहले बातचीत होनी चाहिए।

प्रमुख समाचार

एक तमिल को भी बनाया जा सकता है देश का पीएमः शाह

नईदिल्ली। तमिलनाडु के एमके स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रधानमंत्री के रूप में तमिलनाडु के व्यक्ति की टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज क्यों हैं। स्टालिन ने आज सलेम में टिप्पणियों के जवाब में कहा कि मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मोदी के प्रति उनका गुस्सा क्या है। अमित शाह ने रविवार को कथित तौर पर तमिलनाडु में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तमिलनाडु का कोई व्यक्ति भविष्य में प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वाली टिप्पणी पर स्टालिन ने जवाब दिया कि अगर भाजपा का विचार है कि एक तमिल को प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो तमिलिसाई सुंदरराजन (तेलंगाना के रायपाल) और एल मुरुगन (केंद्रीय मंत्री) हैं।

मोदी के खिलाफ टिप्पणी, राहुल गांधी को पेशी से मिली छूट

नईदिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी पर मानहानि की शिकायत में अदालत में पेश होने से मिली अंतरिम राहत को 2 अगस्त तक बढ़ा दिया। शिकायतकर्ता, जो भाजपा कार्यकर्ता होने का दावा करता है, ने आरोप लगाया था कि राफेल लड़ाकू जेट सौदे के संदर्भ में गांधी की कमांडर-इन-चोर टिप्पणी मानहानि के समान है। न्यायमूर्ति एस वी कोतवाल की एकल पीठ ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद 2021 में स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा, पहले दी गई अंतरिम राहत दो अगस्त तक जारी रहेगी। इससे पहले, गांधी को महेश श्रीश्रीमल द्वारा दायर मानहानि शिकायत में नवंबर 2021 में स्थानीय अदालत द्वारा उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था।

अदालत के फैसले को लेकर आशान्वितः शुभेंदु अधिकारी

नईदिल्ली। भेंदु अधिकारी ने कहा कि पहले हाफ में ढाई घंटे तक कोर्ट की सुनवाई सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा कि कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता (जैसा कि मैं याचिकाकर्ता हूं) सुनवाई को रोकना नहीं चाहता। बल्कि वे चुनाव चाहते हैं, जिसमें सभी की भागीदारी के साथ और पूरी तरह से भयमुक्त माहौल में चुनाव हो। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पंचायत चुनाव मामले में कलकत्ता उच न्यायालय की भूमिका को लेकर आशान्वित हैं। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और कांग्रेस सांसद अधीर चौधरी ने नामांकन की समय सीमा बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर कलकत्ता उच न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई 12 जून को हुई । हालांकि सुनवाई पर फैसला अभी सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया है।

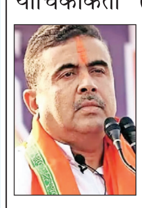

लैब में ही चीन ने बनाया था कोरोना वायरस, बड़ा खुलासा

नईदिल्ली। तीन साल से अधिक समय पहले कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से इस बात पर बहस होती रही है कि क्या वायरस प्रयोगशाला में रिसाव के कारण उभरा है या ये प्रकृति से आया है। जिन शोधकर्ताओं ने इन वर्षों में उत्तर खोजने का प्रयास किया है, वे चीन के पारदर्शिता की कमी को उजागर भी करते रहे हैं, जिस देश से वायरस पहली बार सामने आया था। हालांकिद संडे टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी वैज्ञानिक खतरनाक प्रयोगों की एक गुप्त परियोजना चला रहे थे, जिसके कारण वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से रिसाव हुआ और कोविड का प्रकोप शुरू हुआ। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस को चीन की वुहान लैब में ही बनाया गया। इसे चीन की सेना के लिए बनाया जा रहा था। संडे टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

बिपारजॉय की स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहा गृह मंत्रालय

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को चक्रवाती तूफान बिपारजॉय को लेकर एक बड़ी समीक्षा बैठक की। माना जा रहा है कि यह चक्रवात बृहस्पतिवार को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में दस्तक दे सकता है। कच्छ, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी में 15 जून सुबह से शाम तक 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ तूफान आ सकता है और हवा की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। चक्रवात बिपारजॉय को लेकर समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संवेदनशील स्थानों में रहने वाले लोगों की निकासी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किए जाएं। उन्होंने कहा कि नुकसान की स्थिति में तत्काल सेवा बहाल करने की तैयारियों के साथ आवश्यक सेवाओं का रखरखाव सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय चक्रवात बिपारजॉय की स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहा है।

प्रियंका गांधी की मध्यप्रदेश के लिए घोषित 5 गारंटी की सूची में ओपीएस भी

पुरानी पेंशन योजना बनेगी आगामी चुनाव का मुद्दा

जितेंद्र भारद्वाज

कांग्रेस पार्टी ने इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के हाथ 10 करोड़ का फॉर्मूला लगा है। पुरानी पेंशन बहाली के इस फॉर्मूले को कांग्रेस पार्टी, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव में परख चुकी है। इन दोनों राज्यों में मिली सफलता के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए ओपीएस के फॉर्मूले को अपने एजेंडे में शामिल करने का निर्णय लिया है। प्रियंका गांधी ने पुरानी पेंशन पर भाजपा की कमजोर कड़ी पकड़ ली है।

हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर प्रियंका गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया था। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे सरकारी कर्मियों की एक बड़ी भूमिका रही है। सोमवार को प्रियंका गांधी ने मध्यप्रदेश में जिन पांच गारंटी की बात कही है, उनमें सरकारी कर्मियों के लिए %पुरानी पेंशन% बहाली भी शामिल है। इस साल मध्यप्रदेश के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने पहले ही पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है।

जो ओपीएस देगा, वही देश पर राज करेगा

केंद्र में स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव और %नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन% (एनजेसीए) के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे की गहराई भाजपा समझ नहीं पा रही है। भाजपा अब भी एनपीएस में सुधार की बात कहती है, जबकि कर्मचारी संगठन कह चुके हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन बहाली से परे कुछ भी मंजूर नहीं है। एनपीएस को समाप्त करना ही पड़ेगा। अब

ओपीएस का मुद्दा हर राज्य में पहुंच चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे का असर देखने को मिलेगा। देश में सरकारी कर्मचारी, पेंशनरों और उनके परिवारों को मिलाकर देखें, तो वह आंकड़ा 10 करोड़ से पार चला जाता है। कर्मचारियों ने पहले भी कहा है कि %जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, वही देश पर राज करेगा।

ओपीएस के पक्ष में नहीं है केंद्र सरकार

केंद्र सरकार, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसे आने वाली पीढ़ियों पर बोझ बता चुके हैं। उन्होंने पुरानी पेंशन को लेकर कहा था कि ऐसा पाप न करें, जो आपके बचों का अधिकार छीन ले। पीएम ने आर्थिक संकट में फंसे एक पड़ोसी मुल्क का उदाहरण भी दिया। देश में कुछ राय आज उसी राह पर चल रहे हैं। वे तत्कालीन भुगतान के चक्कर में देश को बर्बाद कर देंगे। अपने फैसलों के द्वारा वे आने वाली पीढ़ियों पर भारी बोझ डाल रहे हैं। इसके बाद कर्मचारी संगठनों और विपक्ष के दबाव में केंद्र सरकार ने इस मामले में जो कमेटी गठित की है, उसके एजेंडे में कहीं भी ओपीएस का जिक्र नहीं है। सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बदलाव के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में चार

एनपीएस में सुधार कर सकती है सरकार

केंद्र सरकार ने कह दिया है, यह कमेटी देखेगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के मौजूदा ढांचे और संरचना के आलोक में, कोई परिवर्तन आवश्यक है। यदि ऐसा है, तो राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय स्थान पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने के लिए उपयुक्त उपायों के लिए सुझाव देना है। इसमें आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखने पर ध्यान दिया जाएगा। कमेटी को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई, उसमें कहीं भी ओपीएस नहीं लिखा है।सदस्यों की कमेटी की है।

कांकेर में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर

बीएसएफ और डीआरजी जवानों ने मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को मार गिराया, रायफल बरामद

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सोमवार सुबह हुई मुठभेड़ में जवानों ने एक महिला नक्सली को मार गिराया। मौके पर जवानों ने एक रायफल भी बरामद की है। फिलहाल इलाके में सर्चिंग जारी है। बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान पहुंचे थे। मामला छोटेबेठिया थाना क्षेत्र का है। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने मुठभेड़ की पुष्टि की है।

हथियारबंद नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर रवाना हुए थे जवान

जानकारी के मुताबिक, पुलिस को छोटेबेठिया क्षेत्र में आरकेबी डिवीजन सचिव, मेंढकी एलओएस कमाण्डर के साथ करीब 20-25 सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद डीआरजी और बीएसएफ 132 बटालियन के जवानों को संयुक्त रूप से कोटरी नदी के पूर्वी क्षेत्र के ग्राम आमातोला, बिनागुण्डा एवं कालपर की ओर ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया।

बीनागुंडा के पास घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग की

गश्त के दौरान जवान आगे बढ़ रहे थे, तभी सुबह करीब 7 बजे बीनागुंडा के पास घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस पर जवानों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे चली मुठभेड़ के बाद नक्सली जान बचाकर भाग निकले। इसके बाद जवानों ने इलाके में सर्चिंग शुरू की। इसमें एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है।

इसी इलाके में कुछ दिन पहले नक्सलियों ने की थी आगजनी

वहीं शव के पास जवानों को 303 बोर की एक राइफल भी बरामद हुई है। अभी तक मारी गई महिला नक्सली की शिनाख्त नहीं हो सकी है। जवान उसका शव लेकर लौट रहे हैं। पांच दिन पहले इसी इलाके में नक्सलियों ने कई वाहनों में आग लगा दी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर यहां नक्सली गतिविधियां बढ़ रही हैं।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद

7 जून को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जंगलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। विवरण के अनुसार, यह कोबरा और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का संयुक्त अभियान था। मुठभेड़ के समय छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिलों के सीमावर्ती इलाकों में कई विस्फोट और गोलियां चलने की भी आवाजें सुनी गईं।

इससे पहले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में दो-दो हजार रुपये मूल्य के पचास नोट (एक लाख रुपये) बरामद कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये रुपये कथित तौर पर एक नक्सली कमांडर के थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी थी। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी।

माड़ (अबूझमाड़ क्षेत्र) के माओवादी कमांडर मल्केश ने अपने कुछ समर्थकों को दंतेवाड़ा के गीदम इलाके में मोटरसाइकिल और अन्य सामान्य खरीदने के लिये भेजा था।

नक्सलियों ने दी सरपंच-उपसरपंच को जान से मारने की धमकी

नारायणपुर। नारायणपुर में एक बार फिर नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर लोगों में खौफभर दिया है। इस बार नक्सलियों के बैनर पोस्टर में सरपंच और उपसरपंच के नाम मौत का फरमान है। रविवार रात नक्सलियों ने ये बैनर पोस्टर चस्पा कर इलाके में सनसनी फैला दी है। क्सलियों ने बैनर पोस्टर में ओरछा विकासखंड में बेसेमेटा गांव के सरपंच और उपसरपंच सहित माइंस खोलने में मदद करने वालों के हाथ पैर काटने के साथ जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल, गांव के नदी में पानी रोकने के लिए डेम निर्माण किया जा रहा था। लेकिन डेम निर्माण के विरोध में बैनर पोस्टर लगाकर नक्सलियों ने इलाके में दहशत फैला दी है। नक्सलियों ने नदी में डेम निर्माण रोकने और माइंस को रोकने के लिए गायता पारा के ग्रामीणों और बेसेमेटा के ग्रामीणों को भी संबोधित किया है। बता दें कि, नारायणपुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहां नक्सली आए दिन क्षेत्र में दहशत बनाने के लिए नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं। विकास विरोधी नीतियों के तहत नक्सली कई बार बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं।

पटवारियों पर प्रशासन का एक्शन, धरना स्थल से उखाड़े पंडाल, घरों के बाहर नोटिस चस्पा

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ में चल रही पटवारियों की हड़ताल को लेकर सरकार के बाद अब प्रशासन भी एक्शन में मूड में आ गया है। कबीरधाम में पटवारियों के धरना स्थल पर लगा पंडाल प्रशासन ने सोमवार के उखड़वा दिया। इसके अलावा उनके घरों के बाहर नोटिस चस्पा कर काम पर लौटने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पटवारी 15 मई से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इसके बाद सरकार ने 7 जून को एस्मा लगा दिया है। यह तीन महीने तक प्रभावी रहेगा।

राज्य सरकार के आदेश के बाद भी जिले के 100 से भी ज्यादा पटवारियों की हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। पटवारी बड़ी संख्या में सुबह से ही राजीव गांधी पार्क स्थित धरना स्थल पर एकत्र थे और प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच दोपहर करीब एक बजे प्रशासन की टीम पहुंची और पटवारियों के लगाए पंडाल को पार्क से हटवा दिया गया। इसके चलते पटवारियों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं घरों के बाहर नोटिस लगाए जाने से भी पटवारी भड़के हुए हैं। उनमें नाराजगी है। जिले के पटवारियों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती हड़ताल पर रहेंगे। इनकी आठ सूत्रीय मांगे हैं।

वेतन विसंगति को दूर कर वेतन में बढ़ोत्तरी की जाए। वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन किया जाए, राजस्व निरीक्षक के कुल पदों में 50% पर पटवारियों के वरिष्ठता के आधार पर और 50% पदों पर विभागीय परीक्षा के आधार पर प्रमोशन किया जाए, साथ ही 5 वर्ष पूर्ण कर चुके पटवारियों को राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण दिलाया जाए। संसाधन और भत्ते की मांग। स्टेशनरी भत्ते की मांग। अतिरिक्त प्रभार के हल्के का भत्ता की मांग। पटवारी भर्ती के लिए योग्यता स्नातक करने की मांग। मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त की जाए। बिना विभागीय जांच के एफआईआर दर्ज ना किया जाए।

राजस्व मंत्री ने मांगे पूरी करने का दिया था आश्वासन

जिलाध्यक्ष पालेश्वर सिंह ठाकुर के बताया कि सभी पटवारी साथी प्रतिदिन धरना स्थल पर शत प्रतिशत उपस्थित हो रहे हैं। यही पुरानी मांगो को लेकर वर्ष 2020 में भी 15 दिन की हड़ताल की गई थी। तब हड़ताल राजस्व मंत्री के आश्वासन बाद स्थगित की गई थी, लेकिन, अभी तक मांग पूरी नहीं की गई। यही कारण है कि सभी पटवारी हड़ताल पर जाने के लिए, मजबूर हुए हैं। जब तक मांगो को सरकार पूरा नहीं करती तब तक मैदान में डटे रहेंगे। इस हड़ताल से जिले में करीब 800 से अधिक प्रकरण पेंडिंग हो गए हैं।

न प्रमाणपत्र बन रहे, न राजस्व के मामले हल हो रहे

शिक्षा सत्र चालू होने वाला है। रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके कारण विद्यार्थियों को जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, लेकिन पटवारियों की हड़ताल के चलते सारे काम ठप पड़े हुए हैं। राजस्व के मामले भी लटके हैं। इन जरूरी दस्तावेजों के नहीं बनने और विद्यार्थियों को आने वाली दिक्कतों को देखते हुए राज्य सरकार ने एस्मा लगाया है। साथ ही कृषि कार्य भी आरंभ होने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांकन, बटांकन और नामांतरण की कार्रवाई शासकीय योजनाओं का लाभ लेने अत्यावश्यक है।

भू-विस्थापित 16 को करेंगे महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव

कोरबा। भू-विस्थापितों के लंबित रोजगार प्रकरणों का निराकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ किसान सभा और रोजगार एकता संघ द्वारा पुनः आंदोलन की तैयारी जुट गया है। कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपते हुए 16 जून को कार्यालय का घेराव व 26 जून को खदान बंद की चेतावनी दी है।

सभा को संबोधित करते हुए माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा कि भू-विस्थापित रोजगार के लंबित प्रकरणों का निराकरण की मांग करते हुए थक गए हैं अब अपने अधिकार को छिन कर लेने का समय आ गया है। विकास के नाम पर अपनी गांव और जमीन से बेदखल कर दिए गए विस्थापित परिवारों की जीवन स्तर सुधरने के बजाय और भी बदतर हो गई है। कोयला खदानों के अस्तित्व में आ जाने के बाद विस्थापित और उनके परिवारों की सुध लेने की सरकार और एसईसीएल के पास समय ही नहीं है। खानापूर्ति के नाम पर कुछ लोगों को रोजगार और बसावट दिया गया। जमीन के बदले पैसा और ठेका नहीं, स्थाई रोजगार देना होगा। छोटे-बड़े सभी खातेदार को नौकरी देना होगा। भू-विस्थापित किसानों के पास अब संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। उल्लेखनीय है कि 31अक्टूबर 2021 को लंबित प्रकरणों पर रोजगार देने की मांग को लेकर कुसमुंडा खेत्र महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष दस से ज्यादा गांवों के प्रभावित 588 दिनों से अनिश्चित कालीन धरना पर बैठे हैं।

किसान सभा के अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर, दीपक साहू, जय कौशिक, भूविस्थापित रोजगार एकता संघ के नेता दामोदर श्याम, रेशम यादव,रघु यादव, सुमेंद्र सिंह कंवर ने कहा कि भू-विस्थापितों को बिना किसी शर्त के जमीन के बदले रोजगार देना होगा। इस दौरान उपस्थित भू-विस्थापितों ने कहा की 16 जून को कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव में प्रभावित गांव के हजारों पीड़ित परिवार समेत करेंगे। इस दौरान बृजमोहन दीननाथ, लंबोदर, जय कौशिक, बसंत चौहान, घनाराम, फिरथ लाल, उत्तम दास, हेमदास, शिवदास, नरेश दास, रामखिलावन, जितेंद्र, होरीलाल,अनिल बिंझवार, हेमलाल, हरिहर पटेल, कृष्णा के साथ प्रभावित भू-विस्थापित उपस्थित रहे।

रोका छेका अभियान शहर में ठप्प, मवेशी असुरक्षित

कोरबा। मवेशियों की सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाला रोका छेका अभियान शहर में ठप हो चुका है। शहरी गोठान और निगम में काऊकेचर उपलब्ध होने के बाद भी सार्वजनिक स्थलों में गाय बैलों का जमावड़ा देखा जा रहा है। यातायात सुरक्षा की दृष्टि से अब कारगर कदम नहीं उठाए जाने सड़के गोठान बन गई है।

प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा बारी के तहत मवेशियों एक सुरक्षित आश्रय स्थल सुरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद भी न केवल मवेशी असुरक्षित हैं बल्कि यातायात व्यवस्था में सुधार नहीं है।

शहर के बुधवारी, सोनालिया चौक, सीतामढ़ी मार्ग, कोसाबाड़ी, घंटाघर ऐसी जगह हैं, जहां चिलचिलाती धूप के बावजूद सड़क बीचो बीच मवेशियों को जुगाली भरते देखा जा सकता है। शहर में गोठान तो बना है लेकिन यह मवेशियों की संरक्षण स्थली नहीं बन सकी। शहर में लंगड़ाते और बीमार मवेशियों को सड़क किनारे सुस्त पड़े देखा जा सकता है। निगम में काऊकेचर होने के बाद भी उन्हे गोठान तक इलाज के लिए नहीं पहुंचाया जा रहा। रोका छेका अभियान शुरू होने से अनुमान लगाया जा रहा था सड़के मवेशियों से मुक्त हो जाएगी। शाम और सुबह के समय मार्ग में आवागमन बढ़ने के दौरान दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। शहर से लगे गांवों में गोठानों की सुविधा नहीं है। नक्टीखार में जमीन की तालाश पूरी नहीं हुई है। जामबहार, सोनपुरी में स्थल चिन्हांकित होने के बाद भी शहर में संचालित बाल गोपाल गऊ सेवा समिति के अध्यक्ष मूलचंद शास्त्री का कहना है कि प्रति माह सड़क दुर्घटना में 20 से 30 मवेशियों की मौत हो जाती है। समिति की ओर से बीमार व दुघटना घायल मवेशियों का पंपहाउस के वनभूमि में इलाज किया जाता है। दुर्घटना ग्रस्त गाय या बैलों को लेने के लिए उनके मालिक नहीं आते। मवेशी पालकों पर निगम प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

भूपेश सरकार खाद उपलब्ध करने में असमर्थ : प्रेमलता

नगरी। भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री व पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमलता नागवंशी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए, बताया की भूपेश सरकार खरीफ फसल में बीज और खाद कई सोसायटियों में उपलब्ध नहीं करा पा रही है। यहाँ तक की कई सोसायटी में राशन भी नहीं मिल रहा है जिसके करण आम जनों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया की यह सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में लगी हुई है। जिस तरह से किसानों को छलने का प्रयास भूपेश सरकार कर रही है वह बहुत ही गलत है, किसान दर दर ठोकरें खा रहा है। वहीं दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 2183? कर दिया है जो की बहुत ही सराहनीय है। निश्चित ही मोदी जी की लोकप्रियता और जनता के लिए कार्य पुनः छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को वापस लाएगी तथा भूपेश सरकार से त्रस्त जनता कांग्रेस को इस बार नकारेगी।

खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि स्वागत योग्य

नगरी। विपणन वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी मिलने पर भाजपा युवा मोर्चा मंडल बेलरगांव के मंडल अध्यक्ष मोरध्वज सेन ने इस निर्णय का स्वागत किया उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को बड़ी राहत देते हुए कई फसलों पर एमएसपी में इजाफा किया गया है। ये बढ़ोत्तरी वित्त वर्ष 2023- 24 की खरीफ की फसलों के लिए की गई (मोदी सरकार की ओर से कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले के मुताबिक तीवर दाल की एमएसपी में 400 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ोत्तरी की गई है (जबकि धान मक्के और मूंगफली में भी बढ़ोत्तरी कि गई है इससे देश में बड़े स्तरों पर किसानों को लाभ होगा।

आषाढ़ की हुई पहली फुहार उमस से लोग हलकान

कोरबा। मौसम ने मानसून आगमन का संकेत दे दिया। आषढ़ माह शुरू होने के सात दिन बाद रविवार की सुबह आसमान में बादल छाने के वर्षा हुई। दोपहर तक बादल साफ होने से धूप का असर फिर तेज गया। वातावरण में उमस होने से लोग हलकान रहे। आषाढ़ माह वर्षा काल की शुरूआत लिए जाना जाता है। सप्ताह भर समय गुजर जाने के रविवार की सुबह हई वर्षा से लोगों ने राहत महसूस किया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए थे। अन्य दिनों की तुलना में सुबह का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के बजाए 35 डिग्री में सिमट गया। अनुमान लगाया जा रहा वर्षा लंबे समय तक जारी रहेगी पर ऐसा नहीं हो सका। आधे घंटे बाद सुबह 10 बजे बदली छंटने से धूप तेज हो गया। दोपहर 12 बजे तक तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। हल्की वर्षा के बाद धूप तेज होने से वातावरण में उमस का असर तेज हो गया। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों धूप छांव के बीच मौसम परिवर्तन का असर जारी रहेगा। तेज धूप से राहत पाने के लिए लोग बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं।

प्री-मेडिकल कोचिंग प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित

कांकेर। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को वर्ष 2023-24 में प्री-मेडिकल तथा प्री-इंजीनियरिंग कोचिंग में प्रवेश के लिए प्रतिभावन विद्यार्थियों से 28 जून तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने जानकारी दी है कि प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी कक्षा 12वीं उत्तीर्ण बोर्ड परीक्षा में जीव विज्ञान एवं गणित विषय के साथ न्यूनतम 70 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा के साथ एक वर्षीय कोचिंग दिलाया जायेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों के पालकों का वार्षिक आय 02 लाख 50 हजार रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय कांकेर में 28 जून सायं 05 बजे तक जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा में प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर किया जायेगा। राज्य के जिस जिले में कोचिंग संस्था का चयन होगा, उसी जिले में कोचिंग संपन्न कराया जायेगा।

आबकारी अमला अवैध शराब की आड़ में भयादोहन में जुटा

कोरबा। जिले का आबकारी अमल अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने के नाम पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का भयादोहन कर रहा है। ठेकेदारों की तर्ज पर जिले भर में कई बाहरी लोगों का उपयोग छापामारी में किया जा रहा है, जो लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने में भी पीछे नहीं रहते। ऐसा ही एक मामला शनिवार को कोरबा में और दूसरा मामला कोरकोमा गांव में हुआ है। जानकारी के अनुसार रामनगर बाईपास रोड कोरबा निवासी कलशमति बंजारे पति लखनराम बंजारे 60 वर्ष के घर पर शनिवार 10 जून 2023 की सुबह करीब 7 बजे आबकारी विभाग के अधिकारी अग्रवाल ने 5 से 6 लोगों के साथ छापा मारा। सभी जबरिया घर के अंदर घुस कर तलाशी लेने लगे। उन्होंने अलमारी सहित किचन, बेडरूम में रखे कपड़ा बिस्तर की तलाशी ली। इसी बीच अलमारी की भी तलाशी ली गई, जिसमें 5000 रुपया नगद रखा हुआ मिला, जिसे शराब बेचते हो कहते हुए बिक्री की रकम बता कर अपने पास रख लिए।

रंजना साहू ने केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओ को सम्मेलन में विस्तारपूर्वक रखा

■ नगरी एवं बेलरगांव मंडल के संयुक्त मोर्चा की बैठक संपन्न

नगरी। भाजपा युवा मोर्चा बेलरगांव मंडल के अध्यक्ष मौर्यध्वज सेन एवं युवा मोर्चा महामंत्री लिलेश प्रजापति के नेतृत्व में धमतरी विधायक रंजना साहू का प्रथम बेलरगांव आगमन होने पर आतिशबाजी के साथ जयकारा लगाते हुए बाईक रैली निकाल कर स्वागत किया गया।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत बेलरगांव मंडल एवं नगरी मंडल का संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन बेलरगांव के साहू सदन में रखा गया जिसमें मुख्य रूप से धमतरी विधायक रंजना साहू, राष्ट्रीय किसान मोर्चा मंत्री एवं पूर्व विधायक पिंकी शिवराज शाह,प्रकाश बैस जिला महामंत्री, जिला मंत्री प्रेमलता नागवंशी, जनपद अध्यक्ष दिनेश्वरी नेताम,मंडल

अध्यक्ष बेलरगांव अकबर कश्यप, नगरी मंडल अध्यक्ष मोहन नाहटा,सासंद प्रतिनिधि कमल डागा उपस्थित हुए। जिसमें संयुक्त मोर्चा बैठक के प्रभारी एवं धमतरी विधायक रंजना साहू ने केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओ को सम्मेलन में विस्तार पूर्वक रखा और सिहावा विधानसभा के वर्तमान विधायक निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य है कि आज सिहावा विधानसभा को ऐसा विधायक मिला है जो जनता की छटनी करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी गांव से उनके पास काम से जाता है तो वह पहले पूछती है कि तुमने किस पार्टी को वोट जाता उसके बाद उसकी सुनवाई होती है विधायक तो पूरी जनता का होता है किंतु जनता के साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल गलत है किसी गांव से उन्हें कम और मिला है तो उस गांव के विकास को धोखा देती है ऐसे विधायक उखाड़ कर फेंकना है और जब विधायक उखाड़ेगी तो पूरा सरकार भी उखड़ कर फेंकी जाएगी। जिसमें राष्ट्रीय किसान मोर्चा मंत्री व पूर्व विधायक पिंकी शिवराज ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि सभी मोर्चा अपने दायित्व का निर्वहन करें एवं तन मन से काम करें तो कोई मुश्किल नहीं है कि हम कांग्रेसी सरकार को उखाड़ कर फेंक पाएं कार्यक्रम में सासंद प्रतिनिधि मोहन पुजारी, महामंत्री मनोहर मानिकपुरी,युवा मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य निखिल साहू, नरसिंह मरकाम,मीडिया प्रभारी रामगोपाल साहू, अनुसूचित जनजाति मौर्चा जिला अध्यक्ष महेन्द्र नेताम, जनपद उपाध्यक्ष हुमिंत लिमजा,युवा मोर्चा मडंल अध्यक्ष नगरी सुनील निर्मलकर, युवा मोर्चा मडंल अध्यक्ष बेलरगांव मौर्यध्वज सेन,महामंत्री युवा मोर्चा लिलेश प्रजापति, चुम्मन साहू, पूर्व मडंल अध्यक्ष शेखर आडील,नगरी मडंल महामंत्री राजेश गोसाई,उमेश साहू,महेन्द्र धनुसेवक,सुलोचना साहु महिला मोर्चा अध्यक्ष, बबीता साहु, सत्यवती नेताम, केशांत गुप्ता, भुवनदास मानिकपुरी, गणेश साहू, अकतु ध्रुव, सीमा देवागंन,प्रीति यदु, कलपना आडील,उमेंद्र दीवान, पोखराज कश्यप, रामसिंह मरकाम, वैदकुमार गंजीर, खेमन साहु, राखी साहु, मनोहर नेताम, राजकुमार नेताम, कुसुमलता सेन सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता थे।

नरसिंगपुर गौठान में बांस हस्त शिल्प निर्माण में रीपा बन रही आजीविका केंद्र

कांकेर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा गांवों में ही रोजगार के बहुआयामी केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से गांवों में रीपा की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना रीपा के अंतर्गत सभी जिलों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से भानुप्रतापपुर विकासखंड के रीपा गौठान नरसिंगपुर में जहां गोबर खरीदी और वर्मी कम्पोस्ट जैसे दोहरे लाभ वाली गोधन न्याय योजना संचालित है, वहीं महिलाएं कृषि और गैर कृषि आधारित आय मूलक कार्य कर रही हैं। यहां के स्थानीय लोगों के हुनर एवं स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका मूलक गतिविधियों के रूप में बांस हस्त शिल्प निर्माण इकाई

की स्थापना की गई है। नरसिंगपुर गांव में 13 से 14 परिवार के लोग पारधी कंडरा समुदाय से है, जिनका पुस्तैनी और पैतृक व्यवसाय दैनिक जीवन मे उपयोग होने वाले बांस से बने वस्तुओं जैसे सुपा, टुकना-टुकनी, सुपेली पाप, बीज बौनी पर्रा, बिजना, हाथ खांडा झाड़ू, मछली थापने के लिए थापा, मुर्गी मछली रखने का पात्र चोरिया झारा इत्यादि बनाई जाती है। क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रवीण कवाची ने बताया कि इन परिवार के महिला सदस्यों को समूह बना कर गोधन न्याय योजना से जोड़ा गया है। रीपा गौठान नरसिंगपुर में शासन द्वारा बांस हस्त शिल्प इकाई का भी निर्माण किया गया है, ताकि गांव के बम्बू क्राफ्ट व्यवसाय से जुड़े इन परिवार के लोगों को गांव में ही रोजगार व उनके द्वारा बांस से निर्मित वस्तुओं के बिक्री के लिए बाजार मिल सके।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मोदी का विरोध करते देश का विरोध करने लगे राहुलः नड्डा

शिमला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कांगड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि भाजपा देश की अकेली पार्टी है जो विचारों पर चलती है, बाकी सभी दल वैचारिक रूप से शून्य हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कुर्सी के लिए ये दल किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार हैं। आज तो सीपीएम और कांग्रेस भी हाथ मिला कर चुनाव में उतरते हैं। कहां गए इन दोनों के विचार? लेकिन भाजपा ऐसी नहीं है। नड्डा ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भ्रष्टाचार से युक्त सरकार में घोटाले ही घोटाले थे लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्कैम से निकल कर स्कीम वाली सरकार देश में बनी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का युवराज देश की गरिमा को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी भारत की परम्पराओं और संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं।

विपक्षी दलों के पीएम उम्मीदवार को लेकर गरमाई सियासत

पटना। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। इससे पहले पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर सियासत गर्म होती नजर आ रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लेकर जेडीयू और भाजपा का बयान सामने आया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि ना किसी को सीएम बनना है और ना किसी को पीएम बनना है। डिप्टी सीएम ने बताया है कि मात्र 2024 का लक्ष्य है। दंगा फसाद करने वाले और देश के इतिहास को बदलने वालों के खिलाफ लड़ाई है। यह इसकी तैयारी चल रही है। वहीं, रविवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। सीएम नीतीश देश को भाजपा मुक्त बनाने में लगे हुए है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया है कि जब, बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी, तो एक बैठक का आयोजन होगा। इसमें सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार का चयन होगा। बता दें कि 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में बेहतर इंतजाम किए जाएंगे।

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले बवाल की आशंका

कोलकाता। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग सख्त हो गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए सभी नामांकन केंद्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है कि नामांकन प्रक्रिया सुरक्षित रूप से संपन्न हो। यह आदेश गुरुवार तक प्रभावी रहेगा। अधिकारी ने कहा कि हमने नामांकन केंद्रों के 1 किमी के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस आशय का एक आदेश एसईसी द्वारा रविवार को जारी किया गया था। पंचायत चुनाव आठ जुलाई को होंगे। एसईसी ने कहा कि केवल दो व्यक्ति नामांकन केंद्र के अंदर कागजात दाखिल करने के लिए कदम रख सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि राज्य भर में पहले दो दिनों में चुनावों के लिए अब तक 10,000 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं।

शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

मुंबई। मुंबई पुलिस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी सागर बर्वे एक निजी फर्म के डेटा फीडिंग और एनालिटिक्स सेक्शन में काम करता है। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधिकारी ने कहा, मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच बर्वे को मुंबई ले आई। उसे अदालत में पेश कर मंगलवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बर्वे ने कथित तौर पर फेसबुक पर शरद पवार के खिलाफ जान से मारने की धमकी पोस्ट की है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने धमकी देने के लिए दो फर्जी अकाउंट बनाए थे। कथित धमकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुलिस को पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश दिया था। फड़नवीस ने भी कहा था कि हालांकि एनसीपी के साथ वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन एक प्रमुख विपक्षी नेता को धमकियां देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अमित शाह के बयान पर कपिल सिब्बल ने दिया जवाब

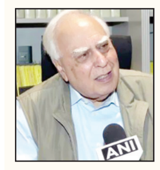

नई दिल्ली। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने सोमवार को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए यूपीए सरकार के दृष्टिकोण की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना का कड़ा प्रतिकार किया। ट्वीट करते हुए सिब्बल ने गृह मंत्री की टिप्पणी से असहमति व्यक्त की और अपने कार्यकाल के दौरान यूपीए सरकार द्वारा उठाए गए दृष्टिकोण का बचाव किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में हुए कारगिल संघर्ष, उरी हमले और पुलवामा हमले सहित देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण चुनौतियों को उजागर करते हुए आरोपों का खंडन किया। सिब्बल ने आगे आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मसूद अजहर को पाकिस्तान पहुंचाने में शामिल थे, जिसके कारण अंततः आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का गठन हुआ। सिब्बल ने दंतेवाड़ा में चल रहे माओवादी हमलों से निपटने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की।

जी20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का विशेष वीडियो संबोधन

डिजिटलीकरण ने भारत में लाया क्रांतिकारी बदलाव

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर जोर दिया और डेटा के डिजिटलीकरण से भारत में लाए गए सकारात्मक बदलावों को दोहराया। जी20 विकास मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डेटा विभाजन को पाटने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण एक महत्वपूर्ण उपकरण है। उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटलीकरण ने एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में हो रही बैठक को संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम रविवार को शुरू हुआ और 13 जून (मंगलवार) को समाप्त होगा।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में एक बहुपक्षवाद- एसडीजी की ओर प्रगति में तेजी लाने के लिए सामूहिक कार्रवाई और दूसरा हरित विकास- एक जीवन शैली (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) दृष्टिकोण पर दो मुख्य सत्र शामिल हैं।

जी20 विकास मंत्रियों की बैठक के लिए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि

काशी सदियों से ज्ञान, चर्चा, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र रही है। इसमें भारत की विविध विरासत का सार है और यह देश के सभी हिस्सों के लोगों के लिए, रूपांतरण बिंदु के रूप में काम करता है। मुझे खुशी है कि जी20 विकास एजेंडा काशी तक भी पहुंच गया है। विकास, वैश्विक दक्षिण के लिए एक प्रमुख मुद्दा है। वैश्विक दक्षिण के देश वैश्विक कोविड महामारी से उत्पन्न व्यवधान से गंभीर रूप से प्रभावित थे और भू-राजनीतिक तनाव के कारण खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट ने एक और झटका दिया है। ऐसी परिस्थितियों में आप जो निर्णय लेते हैं उसका बहुत महत्व होता है।

जी20 की बैठक में एस जयशंकर ने कहा- दुनियाभर में बढ़ीं चुनौतियां

वाराणसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि आपूर्ति श्रृंखला में बाधा, कर्ज संकट और ऊर्जा, खाद्य एवं उर्वरक सुरक्षा संबंधी दबाव के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही है। विदेश मंत्री ने चुनौतियों से वैश्विक एकजुटता की अपील की। वाराणसी में जी20 की विकास मंत्रियों की एक बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने ये बातें कहीं। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने टिकाऊ विकास लक्ष्यों के लिए महत्वकांक्षी सात वर्षीय कार्य योजना तैयार की है, जिसमें जी20 गतिविधियों के लिए समावेशी रोडमैप पेश किया गया है। इसके तहत डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत ढांचा विकास, महिलाओं की बेहतरी के लिए निवेश और ऊर्जा संसाधनों पर फोकस किया गया है। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया आज अभूतपूर्व संकटों का सामना कर रही है और हर दिन अधिक परिवर्तनशील और अनिश्चित होता जा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि कई देशों में महंगाई, ब्याज दर और राजकोषीय घाटे का प्रभाव पड़ा है और गरीब तबका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। एस जयशंकर ने कहा कि हम आज जो फैसला करेंगे, उसमें भविष्य को समावेशी, टिकाऊ और लचीला बनाने की क्षमता होगी। बता दें कि 11-13 जून तक जी20 की विकास मंत्रियों की बैठक का आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है।

प्रियंका गांधी ने मध्यप्रदेश में पांच गारंटी का किया ऐलान

भाजपा पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

जबलपुर। कर्नाटक में शानदार जीत के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सबसे पहले ग्वारीघाट पहुंचीं और नर्मदा पूजा की। वाड्रा के साथ कांग्रेस नेता कमलनाथ भी थे। इसके बाद प्रियंका गांधी ने जबलपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भाजपा और उसकी मध्य प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर बताया।

भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इनके दिलों में आपके लिए कोई आस्था नहीं है। यहां आकर घोषणाएं करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी बाते होती हैं, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बाते होती हैं। ये हिमाचल और कर्नाटक में भी यही कहते थे। जनता ने इन्हें दिखा दिया कि ये डबल इंजन की बाते बंद करो और काम करो नहीं तो निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापम घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई-टेंडर घोटाला, टीवी सेट वितरण घोटाला। इन्होंने नर्मदा मैया और महाकाल कॉरिडोर को भी नहीं छोड़ा।

जबलपुर में रैली में प्रियंका ने कहा कि भाजपा शासन ने पिछले तीन वर्षों में राज्य में केवल 21 सरकारी नौकरियां दी हैं। यह आरोप लगाते हुए कि पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रियंका ने कहा कि भाजपा चुनावों के दौरान बड़े-बड़े वादे करती है लेकिन उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं करती है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के घोटालों की सूची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस के लिए कहे गए अपमानों की संख्या से अधिक लंबी है, कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को कांग्रेस द्वारा फर्जी गारंटियों के

खिलाफ चेतावनी देने वाली टिप्पणी के संदर्भ में। प्रियंका ने उज्जैन शहर में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थापित सप्तऋषियों के ढहने पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा ने भगवानों को भी नहीं बख्शा है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी ने पवित्र महाकाल को भी अपनी लूट से दूर नहीं रखा।

पांच गारंटी- हर महिला को हर महीने 15 सौ रुपए मिलेंगे। एक हजार का सिलिंडर 500 रुपये में मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। किसानों के कर्ज को माफ करेंगे। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट तक हाफ।

जबलपुर रैली से पहले प्रियंका ने नर्मदा नदी की पूजा-अर्चना की

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोमवार को जबलपुर पहुंचने के बाद मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी की पूजा अर्चना की। इसके बाद वह साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत एक रैली से करेंगी। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। प्रियंका की यात्रा के लिए शहर में कई जगह बजरंगबली के कट आउट लगाए गए हैं। स्थानीय विधायक तरुण भनोट ने प्रियंका गांधी को भगवान गणेश की मूर्ति भेंट की। नेताओं ने नर्मदा नदी को स्वच्छ रखने का संकल्प भी लिया।

22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे प्रधानमंत्री

नईदिल्ली। भगवान राम के भक्तों का एक दशक का लंबा इंतजार जनवरी 2024 में खत्म होने जा रहा है। जनवरी में नवनिर्मित राम मंदिर में राम लला की %प्राण प्रतिष्ठा% की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सूत्रों के अनुसार मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगिराज श्यामशिला (चट्टान) से भगवान रामलला की मूर्ति का निर्माण करेंगे।

राम मंदिर निर्माण को लेकर मंदिर ट्रस्ट की दो दिवसीय अनौपचारिक बैठक हुई, जिसमें राम मंदिर में भगवान राम लला के अभिषेक को लेकर अहम चर्चा हुई। इससे पहले समिति ने राम जन्मभूमि परिसर और रामसेवकपुरम का निरीक्षण किया। ट्रस्ट की ओर से जानकारी दी गई है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए विद्वानों से राय मांगी गई है। रामलला की मूर्ति बनाने पर भी फैसला लिया गया, जिसके लिए मूर्तिकार अयोध्या पहुंच गए हैं। बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, उडुपी पीठाधीश्वर विश्व तीर्थ प्रसन्नाचार्य, कामेश्वर चौपाल, अयोध्या नरेश विमलेंद्र मोहन मिश्र, डॉ. अनिल मिश्रा व निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास सहित ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंददेव गिरि भी मौजूद रहे।

ट्रस्ट की बैठक में हुआ था बड़ा फैसला इससे पहले श्रीराम जन्मभूमि तीरथ क्षेत्र ट्रस्ट का न्यासी बोर्ड ने कहा था कि वह सप्ताह भर चलने वाले प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करेगा। इसी दौरान अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सप्ताह भर चलने वाला समारोह जनवरी 2024 में मकर संक्रांति से या उसके एक दिन बाद शुरू होगा। ट्रस्ट प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए एक शुभ तिथि तय करने के लिए प्रसिद्ध ज्योतिषियों से परामर्श कर रहा है।

खेल
प्रमुख समाचार

वनडे विश्व कप में 15 अक्टूबर को पाकिस्तान से मुकाबला

नईदिल्ली। भारतीय टीम वनडे विश्व कप में अपने अभियान का आगाज आठ अक्टूबर को आस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में करेगी जबकि एक सप्ताह बाद पाकिस्तान के खिलाफ मैच अहमदाबाद में होगा। बीसीसीआई के कार्यक्रम के ड्राफ्ट में यह जानकारी दी गई। ईएसपीएन क्रिकइन्फो ने सोमवार को लिखा, 'बीसीसीआई ने कार्यक्रम का ड्राफ्ट आईसीसी को भेजा है जिसने प्रतिभागी देशों के पास फीडबैक के लिये इसे भेज दिया है। अंतिम कार्यक्रम की घोषणा अगले सप्ताह की जायेगी।' शुरूआती ड्राफ्ट के अनुसार टूर्नामेंट पांच अक्टूबर को शुरू होगा जिसमें मौजूदा चैम्पियन इंग्लैंड का सामना पिछले उपविजेता न्यूजीलैंड से अहमदाबाद में होगा। फाइनल भी 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जायेगा। सेमीफाइनल 15 और 16 नवंबर को होंगे जिनका वेन्यू अभी तय नहीं है। मेजबान भारत अपने लीग मैच नौ शहरों में खेलेगा जिनमें कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरू शामिल है। पाकिस्तान से मुकाबला 15 अक्टूबर को होगा। वहीं पाकिस्तान के लीग मैच पांच शहरों में होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, 'पाकिस्तान छह और 12 अक्टूबर को हैदराबाद में क्वालीफायर दौर से आई दो टीमों से खेलेगा। इसके बाद बेंगलुरू में आस्ट्रेलिया (20 अक्टूबर), चेन्नई में अफगानिस्तान (23 अक्टूबर), दक्षिण अफ्रीका (27 अक्टूबर), बांग्लादेश से कोलकाता में (31 अक्टूबर), न्यूजीलैंड से बेंगलुरू में (पांच नवंबर) और इंग्लैंड से कोलकाता में (12 नवंबर) खेलेगा। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच 29 अक्टूबर को धर्मशाला में और इंग्लैंड से चार नवंबर को अहमदाबाद में होगा। टूर्नामेंट में दस टीमें भाग ले रही हैं जिनमें से आठ तय हैं और दो क्वालीफायर से आयेंगी। टूर्नामेंट में कुछ ही महीने रह गए हैं और अभी तक कार्यक्रम का ऐलान नहीं हुआ है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 99 अंक उछला निफ्टी 18,600 के पार

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच आज घरेलू शेयर बाजार में लगातार दो दिन से जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। आईटी शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी आई और कारोबार के अंत में शेयर बाजार बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुए। आज के कारोबार में सेंसेक्स 99 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी ने भी 38 अंकों की बढ़त दर्ज की। कारोबार के अंत में निफ्टी 18,601.50 पर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 99.08 अंक यानी 0.16 फीसदी की बढ़त के साथ 62,724.71 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 62,804.89 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 62,615.20 तक आया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 38.10 अंक यानी 0.21 फीसदी चढ़ा।

भारत की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंची

नई दिल्ली। भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) सोमवार को 3.75 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े पर पहुंच गया। प्रमुख विकास संकेतक 2023 में 3.75 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो 2014 में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर था। केंद्रीय वित्त मंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट में इसकी पुष्टि की। ट्वीट में कहा गया, भारत की जीडीपी 2023 में 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो 2014 में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर थी। इस तरह भारत दुनिया की 10 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत को अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्ज्वल स्थान के रूप में जाना जाता है। भारत का जीडीपी वर्तमान मूल्य के संदर्भ में 3,737 अरब डॉलर है, जो सिर्फ अमेरिका (26,854 डॉलर), चीन (19,374 अरब डॉलर) और जर्मनी (4,309 अरब डॉलर) से कम है।

डीवीसी 2030 तक बिजली उत्पादन दोगुना करेगीः चेयरमैन

नईदिल्ली। दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के चेयरमैन राम नरेश सिंह ने कहा कि कंपनी अगले सात साल में अपना वार्षिक बिजली उत्पादन दोगुना करेगी। सिंह ने कहा कि 2030 तक 15,000 मेगावाट वार्षिक बिजली उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 7,000 मेगावाट की वर्तमान क्षमता में 8,000 मेगावाट क्षमता और जोड़नी होगी। उन्होंने कहा कि कंपनी नए बिजली प्लांटों की स्थापना के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। सिंह ने रविवार को यहां संवाददाताओं से कहा कहा, 'केंद्र ने छह्हट को 8,000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले नए बिजली प्लांट स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।' उन्होंने कहा कि इसके लिए, तीन ताप विद्युत प्लांट और दो सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जाएंगे।

यूबीएस ने क्रेडिट सुइस का अधिग्रहण पूरा किया

नई दिल्ली। स्विस बैंक यूबीएस ने सोमवार को कहा कि उसने संकटग्रस्त स्थानीय प्रतिद्वंद्वी क्रेडिट सुइस का आपातकालीन अधिग्रहण पूरा कर लिया है। यह 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से सबसे बड़ा बैंकिंग सौदा है, जिससे वह 1.6 ट्रिलियन डॉलर की बैलेंस शीट के साथ एक विशाल बैंक बन गया है। स्विस समाचार पत्रों में प्रकाशित एक खुले पत्र में यूबीएस के सीईओ सर्जियो एर्मोट्टी और चेयरमैन कोल्म केलेहर ने कहा, यूबीएस, स्विट्जरलैंड के लिए एक वित्तीय केंद्र और वैश्विक वित्तीय उद्योग के रूप में यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। मेगा समूह दुनिया के सबसे बड़े धन प्रबंधक यूबीएस को प्रमुख बाजारों में एक अग्रणी स्थान प्रदान करते हुए 5 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति की देखरेख करेगा।

दो हजार के नोट वापसी से अर्थव्यवस्था को लाभ

डॉ. अश्विनी महाजन

नवंबर 2016 की शाम आठ बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में पांच सौ और एक हजार रुपये के नोटों की वैधता को समाप्त करने का निर्णय लोगों से साझा किया, तो पूरा देश चकित हो गया था। पर कठिनाइयों के बावजूद आम जनता ने इसका भरपूर समर्थन किया। हालांकि विपक्षी दलों ने इस बाबत जोर-शोर से विरोध किया। कुछ कठिनाइयों के बाद देश में नगदी बहाल हुई, परंतु देश में वैधानिक नकदी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए केंद्र सरकार ने पांच सौ और एक हजार के पुराने नोटों के बदले पांच सौ और दो हजार के नये नोटों का चलन शुरू किया।

उस समय देश में कुल 17.74 लाख करोड़ की मुद्रा जनता के पास थी, जिसमें से 85 प्रतिशत पांच सौ और एक हजार के नोटों के रूप में थी। पांच सौ के नोटों के मुद्रण में देरी के कारण दो हजार के नोटों को जारी करना सरकार और रिजर्व बैंक की मजबूरी थी। मार्च 2018 तक दो हजार के नोट 6.73 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गये थे। बड़े नोटों के विमुद्रीकरण के नाम पर दो हजार के नोट का जारी किया जाना विमुद्रीकरण की भावना के ही विरुद्ध था। इसलिए मार्च 2018 से ही दो हजार के नोटों की वापसी शुरू हो गयी थी। प्रारंभ में चलन में आये 6.73 लाख करोड़ रुपये के दो हजार के नोट मार्च 2023 तक मात्र 3.62 लाख करोड़ तक ही रह गये। रिजर्व बैंक का कहना है कि दो हजार के कुल जारी नोटों में से 89 प्रतिशत मार्च 2017 से पहले जारी किये गये थे, जो वैसे भी अपना समय काल पूरा कर चुके हैं। तो दो हजार के नोटों की वापसी को अचानक लिया गया निर्णय नहीं कहा जा सकता। विपक्षी दलों का

कहना है कि, सरकार का दावा सही सिद्ध नहीं हुआ कि विमुद्रीकरण का मकसद डिजिटल भुगतानों द्वारा 'लेस कैश' अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ना था। विमुद्रीकरण के समय देश में कुल 17.74 लाख करोड़ की नगदी जनता के पास थी, जो दिसंबर 2022 तक बढ़कर 32.42 लाख करोड़ तक पहुंच गयी। पर समझना होगा कि 2015-16 में देश में चालू कीमतों पर जीडीपी मात्र 135 लाख करोड़ रुपये थी, जो 2022-23 में बढ़कर 272 लाख करोड़ पहुंच गयी। समझा जा सकता है कि जीडीपी के अनुपात में नगदी, पूर्व के 13.14 प्रतिशत से घटती हुई अब 11.91 प्रतिशत तक आ गयी है। यानी डिजिटलीकरण के कारण देश में 'कैश' का चलन कम हो गया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि आम जनता के पास दो हजार के बहुत कम नोट हैं। तो दो हजार के जो नोट चलन में हैं, वे अधिकतर उन लोगों के पास हैं, जिन्होंने अपने धन को नकदी में रखा हुआ है। रिजर्व बैंक की मानें, तो इस निर्णय से बैंकों की जमा में भारी वृद्धि हो जायेगी, सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता भी आयेगी।

विरोधियों का तर्क है कि विमुद्रीकरण से छोटे उद्यमियों को नुकसान हुआ, रोजगार घटे और अर्थव्यवस्था को हानि पहुंची। लेकिन आंकड़ों की मानें, तो 2015-16 के बाद से अब तक के लगभग छह वर्षों में चालू कीमतों पर जीडीपी 135 लाख करोड़ से बढ़कर 272 लाख करोड़ से अधिक हो गयी है। देश के निर्यात 2013-14 में 465.5 अरब डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 767 अरब डॉलर हो गये। कृषि, सेवा, उद्योग सभी क्षेत्रों में प्रगति दिखाई दे रही है। सरकारी मदद से ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए आवास, इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय समावेशन की व्यवस्था हो रही है। सभी इस ओर इंगित करते हैं कि अर्थव्यवस्था बिना बाधाओं के आगे बढ़ रही है। विमुद्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ मुद्रास्फीति के संदर्भ में हुआ है। विमुद्रीकरण के बाद के छह वर्षों (दिसंबर 2016 से नवंबर 2022 के बीच), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (उपभोक्ता मुद्रास्फीति) में केवल 32.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उससे पहले के छह वर्षों (दिसंबर 2010 से नवंबर 2016 के बीच) में यह वृद्धि 54.1 प्रतिशत थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नोटबंदी के कारण देश में बड़े पैमाने पर विदेशों, खासकर शत्रु देशों से आ रहे नकली नोट चलन से बाहर हो गये।

बिहार में उद्घाटन से पहले ही पुल क्यों गिर जाते हैं?

रंजीत कुमार

1710 करोड़ रुपए के बजट से बन रहा बिहार का अगवानी-सुल्तानगंज गंगा महासेतु अपने आप, खड़े-खड़े पल भर में नदी में समा गया। पुल लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका था और कुछ महीने बाद ही इसका उद्घाटन होने वाला था। जिस तरह यह पुल गिरा उस तरह तो रेत की भी कोई दीवार कभी नहीं गिरी होगी। निर्माणाधीन पुल के गिरने से बिहार की सरकारी मशीनरी, उपयोग में लाई जा रही तकनीकी और सामग्री तथा निगरानी तंत्र सवालों के घेरे में है। लोग पूछ रहे हैं कि जनता के अरबों रुपए की इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है? इसका उत्तर देने में बिहार सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही। हां, जांच के आदेश दे दिए गए है, निर्माता कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी दे दिया गया है और सप्ताह भर में ही हमेशा की तरह मामले को ठंढे बस्ते में जाने लायक बनाया जा चुका है।बहरहाल, मामला सनसनीखेज है, लोगों के संज्ञान में है तो राजनीतिक बयानबाजी में कोई कमी नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शाब्दिक युद्ध जमकर चल रहा है। भाजपा ने इस मामले की जांच सीबाआई से कराने की मांग की है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने प्रेस कान्फ्रेंस कर कहा कि, %जब बालासोर रेल दुर्घटना की जांच सीबीआई से करायी जा सकती है, तो बिहार में निर्माणाधीन महासेतु के बार-बार ढहने की जांच भी तकनीकी कमेटी के साथ-साथ सीबीआई से भी होनी चाहिए। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा, इस पुल के घटिया निर्माण की बात बार-बार सदन में उठाई गई। सरकार ने कहा था जांच होगी। बड़े अधिकारी कमीशन लेकर सरकार तक पहुंचाते हैं। नीतीश कुमार में हिम्मत नहीं कि न्यायिक जांच कराए क्योंकि इसमें जो लिप्त हैं वे सरकार में हैं। विपक्ष के जवाब में सत्ताधारी पक्ष की ओर से राजद नेता और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर ही आरोप मढ़ दिया। उन्होंने कहा, सीबीआई वाले इंजीनीयर तो हैं नहीं कि इसकी जांच करेंगे। वहीं तेजस्वी के बड़े भाई और मंत्री तेज प्रताप यादव तो यहां तक कह गये कि, हम पुल बना रहे हैं और भाजपा गिरा रही है। हर बार की तरह मामला दो-चार दिनों के आरोप-प्रत्यारोप के बाद ठंडा हो गया है। लेकिन कई गंभीर सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सरकार को ढूंढना ही चाहिए। पहला सवाल यह है कि बिहार में उद्घाटन से पहले ही बार-बार पुल क्यों गिर जाते हैं। गौरतलब है कि पिछले कोई एक-डेढ़ साल में ही राज्य में चार बड़े पुल या बड़ी संरचनाएं निर्माण के दौरान या उद्घाटन से ठीक पहले ध्वस्त हुए हैं। दिसंबर, 2022 में बेगुसराय में बूढ़ी गंडक पर निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया था। पिछले साल ही नवंबर में नालंदा जिले में एक बड़ा पुल निर्माण के दौरान धाराशायी हो गया जिसमें एक मजदूर की मौत भी हो गई थी। किशनगंज और सहरसा में भी कुछ समय पहले बड़ी लागत से बन रहा पुल और फ्लाईओवर गिर गया था। लेकिन कभी भी न तो इसका कारण सार्वजनिक हुआ न ही निर्माता कंपनी पर कोई ठोस कार्रवाई हुई। अगवानी-सुल्तानगंज महासेतु तो 14 महीने के अंदर ही दो बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। 30 अप्रैल 2022 को पुल के पिलर नंबर 4, 5 और 6 का हिस्सा गिरा गया था। इसके बाद इसकी जांच की जिम्मेदारी आईआईटी रूड़की की एक विशेषज्ञ टीम को दी गई थी। लेकिन जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अनवरत काम चलता रहा। जबकि अनाधिकारिक रूप से यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि पुल के डिजाइन में दोष है। गौरतलब है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी इस पुल का निर्माण कर रही है, बिहार में उसका रिकॉर्ड खराब रहा है।

बेटी को कमान, भतीजा आलाकमान

समीर चौगांवकर

जून 2022 में एकनाथ शिंदे अपनी ही पार्टी शिवसेना के 39 विधायकों के साथ विद्रोह कर उद्धव सरकार को गिराकर खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। उस समय शरद पवार के भतीजे और राज्य के उपमुख्यमंत्री रहे अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच कहा था कि अगर उनके भाजपा के साथ जाने को शरद पवार साहब ने समर्थन दिया होता तो आज हमें सत्ता से बाहर नहीं होना पड़ता और पूरे पांच साल हम सत्ता में रहते। शरद पवार सरकार गिरने का अफसोस मना रहे थे तो उनके भतीजे अजीत पवार भाजपा के साथ न रह पाने का अफसोस मना रहे थे। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार हर सप्ताह इस बात पर अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी कोई शिंदे उभरने वाला है? इशारा अजीत पवार की ओर था और शरद पवार भी भतीजे के बयानों और मीडिया की लगातार अटकलों से परेशान थे और इसका कोई स्थायी समाधान चाह रहे थे। एनसीपी और एमवीए नेतृत्व की तरफ से एक के बाद एक बयानों ने इन अफवाहों को हवा दी कि पवार के भतीजे और विधानसभा में नेता विपक्ष अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी का एक खेमा बगावत कर सकता है और महाराष्ट्र की भाजपा सरकार से हाथ मिला सकता है।

लेकिन शरद पवार ऐसे सियासी सुजान है जो किसी भी मुश्किल वक्त से सकुशल बाहर निकल आने का माद्दा रखते है। 80 वर्ष की उम्र पार कर लेने के बाद भी अपने राजनीतिक तरकश में वो ऐसे कई तीर रखते हैं जो उचित समय पर विरोधियों पर चलाने के लिए होते हैं। ऐसा ही एक तीर शरद पवार ने 2 मई को राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अपने भतीजे अजीत पवार पर लगाम लगाने के लिए चला था। शरद पवार के इस कदम को अजीत पवार के साथ सियासी शतरंज में उनकी चाल के तौर पर देखा गया। अपने इस्तीफे की घोषणा शरद पवार ने अपनी आत्मकथा के नए संस्करण के विमोचन के मौके पर उस वक्त की जब अजीत पवार भाजपा के साथ हाथ मिलाने की रणनीति को अंतिम रूप देने में व्यस्त थे। शरद पवार ने अपने समर्थकों को हैरानी में डालते हुए कहा था कि वे राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। शरद पवार ने आगे कहा कि वे अपना राज्यसभा का कार्यकाल पूरा करेंगे लेकिन भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेगे। लगे हाथ शरद पवार ने नया अध्यक्ष चुनने के लिए एक कमेटी भी बना दी।

शरद पवार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझने वाले जानते थे कि शरद पवार का इस्तीफा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व बदलने का मामला नहीं है, बल्कि शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच गहरे हो चुके अंदरूनी सत्ता संघर्ष की उपज है। असल में शरद पवार ने इस्तीफे का दांव चलकर अजीत पवार को अलग-थलग करने का इमोशनल कार्ड खेला था। शरद पवार जानते थे कि उनके इस्तीफे के बाद पार्टी उनके पीछे गोलबंद हो जाएगी और अजीत पवार को बता दिया जाएगा कि असली बॉस कौन है। हुआ भी वही। पार्टी के तमाम नेताओं के मान मनौव्वल के बाद शरद पवार ने 5 मई को अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे को वापस लेकर बता दिया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की असली ताकत कौन है। 5 मई को अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेकर अजीत के पार्टी तोड़ने की संभावनाओं पर विराम ही नहीं लगाया बल्कि एक महीने बाद 10 जून को पार्टी के 25 वें स्थापना दिवस पर अपनी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले और अपने भरोसेमंद प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अपने भतीजे को पार्टी के भीतर अपनी हैसियत से भी अवगत करा दिया।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष का पद बनाया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद सुप्रिया अब पार्टी के भीतर शरद पवार के बाद दूसरे नंबर की हैसियत में आ गई है। अभी तक महाराष्ट्र से जुड़ा फैसला शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील की सलाह से करते थे। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जब से राजनीति में सक्रिय हुई हैं तब से उन्हें दिल्ली की राजनीति की दीक्षा दी गई है। शरद पवार ने सुप्रिया को अपनी सीट बारामती से सांसद बनाया और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय किया। दिल्ली में जब भी शरद पवार के घर विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई, सुप्रिया सुले ने घर आने वाले नेताओं के चाय पानी की व्यवस्था देखने के साथ दिल्ली के दावंपेचों को समझने की कोशिश भी की। यह बात अलग है कि राजनीति में इतने साल गुजारने और शरद पवार की राजनीति को करीब से देखने के बाद भी सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति में अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। शरद पवार ने सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष और महाराष्ट्र का प्रभार देकर भी यह साफ कर दिया है कि बेटी भतीजे से बढ़कर है और वही उनकी राजनीतिक वारिस होगी।

अजीत पवार के लिए फिलहाल संकेत साफ है कि पार्टी में अजीत पवार को हर फैसले के लिए अपनी छोटी बहन और राजनीतिक अनुभव में भी बहुत छोटी सुप्रिया सुले से अनुमति लेनी होगी। सुप्रिया सुले के महाराष्ट्र के भी प्रभारी होने के नाते आने वाले नगरीय निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव और उसके तुरंत बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में सुप्रिया सुले की मुहर अंतिम होगी। अजीत पवार सिर्फ विधानसभा में विपक्ष के नेता बनकर रह गए हैं। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजीत पवार के समर्थक एक नेता ने शरद पवार के इस निर्णय पर व्यंग करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में अजीत पवार के बिना पत्ता हिलेगा नहीं और दिल्ली में करने के लिए कुछ है नहीं। ऐसे में कोई भी कार्यकारी अध्यक्ष बन जाए फैसला तो अजीत दादा को लेना है और पार्टी को उसे मानना है। अजीत पवार को दरकिनार करने की कोशिश करने वाले शरद पवार भी अजीत पवार की विधायकों में पकड़ से वाफिक है। शरद पवार भी इस बात को जानते हैं कि वह एक सीमा से अधिक अपने भतीजे को अलग थलग करने का जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि ज्यादातर विधायकों की वफादारी अजीत के साथ है। इसीलिए शरद पवार कह रहे हैं कि अजीत पवार के पास विपक्ष के नेता की बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसे में उनको सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल से कम आंकना ठीक नहीं है।

भले ही शरद पवार ने अपनी बेटी को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर यह संकेत दिए हों कि आने वाले समय में उनकी बेटी ही पार्टी की सर्वेसर्वा होगी, लेकिन पार्टी को टूट से बचाना है तो उन्हें आने वाले दिनों में अपने महत्वाकांक्षी भतीजे को भी भरोसे में लेना होगा। हालांकि अजीत पवार को भले ही सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का निर्णय रास न आ रहा हो लेकिन पार्टी से बगावत करना अजीत पवार के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। अजीत पवार के एक करीबी नेता का कहना है कि अजीत पवार के भाजपा में शामिल होने की संभावना नहीं के बराबर है लेकिन वह भाजपा के साथ गठबंधन में उत्सुक हो सकते हैं। लेकिन अजीत पवार इस बात को समझते हैं कि शरद पवार की मजबूत पकड़ वाले पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में शरद पवार से पंगा लेकर जीतना आसान नहीं होगा। अजीत पवार का राजनीतिक क्षेत्र वही है जो शरद पवार का क्षेत्र है। दोनों नेताओं का मतदाता आधार भी साझा है। ऐसे में शरद पवार को भरोसे में लिए बगैर अजीत पवार का कोई भी कदम उनको राजनीतिक रूप से महत्वहीन कर सकता है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

गरुडोपनिषद् (भाग-7)

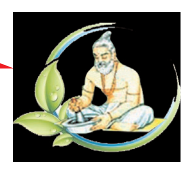

गतांक से आगे...

(ये) अनन्तक, वासुकि, तक्षक, कर्कोटक, पद्मक, महापद्मक, शङ्खक, गुलिक, पौण्ड्रकालिक आदि सभी नाग तथा अन्य सभी दिव्य महानाग एवं महानागों के आदि रूपों वाले, विषैले चञ्चु (चोंच) वाले, विषैले दाँत वाले, विषैले दाढ़ वाले, विषैले अंगों वाले, विषैली पूंछ वाले, सभी जगह विचरण करने वाले, विषैले वृश्चिक (बिच्छू), मकड़ी, प्रकृष्ट (बड़ी) मकड़ी, मूषिका (चुहिया), गृहगौलिक (प्र), गृह गोधिका (छिपकली), घोटक (घृणा उत्पन्न करने वाले विषैले कीटाणु), घरों में स्थित फर्श, दीवारों के छोटे-छोटे छिद्रों आदि में रहने वाले कालानल (विषैले कीड़े), चींटी-चींटे, दीमक आदि उत्पन्न होने वाले, तृण, पत्तों, काष्ठ, पेड़, वृक्षों के कोटर (पोले स्थान) आदि में स्थित रहने वाले, जड़, तना, वृक्ष आदि के छाल, पत्ते, पुष्प एवं फलों आदि से उद्भूत होने वाले विषैले दुष्ट कीट, बन्दर, कुत्ते, बिल्ली, सियार, व्याघ्र (बघरी), वराह आदि विचरण करने वाले विषैले जानवर, जरायुज (पशु-मनुष्य आदि), अण्डज (अण्डों से उत्पन्न), उद्भिज्ज (पेड़-पौधे) एवं स्वेदज (पसीने से प्रादुर्भूत प्राणी), शस्त्र (हाथ से लेकर प्रहार करने वाले), बाण (फेंककर मारने वाले) आदि से क्षत-विक्षत अंग, फोड़े, घाव एवं बड़े घावों से प्रकट होने वाले बड़े कीटक, कृत्रिम एवं अन्य विष, भूत, बेताल, कूष्माण्ड, प्रेत, पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि भय प्रदान करने वाले, विषैली चंचु (चोंच) वाले, विषैले दाढ़ वाले, विषैले अंगों वाले, विषैली पूँछ वाले हों, परन्तु) विषों की विष अर्थात् विष नाशक (वह ब्रह्मविद्या) समस्त विषों को दूषित करने वाली विषों को शोषित करने वाली विषों को विनष्ट करने वाली, विषों को हरण करने वाली है। (वह ब्रह्मविद्या) इन सभी विषों को मारे, नष्ट करे। उस (ब्रह्मविद्या) ने इन घातक विषों को, अन्तलन छिपे हुए विष को, प्रणाशक विषों को नष्ट कर दिया है। इन सभी विषों को विनष्ट करने में इन्द्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है, स्वाहा।

जो साधक (मनुष्य) इस ब्रह्मविद्या का अमावस्या के दिन पाठ करता या श्रवण करता है, उसका जब तक जीवन रहता है, तब तक उसे सर्प (आदि विषैले जन्तु) नहीं काटते। (इस ब्रह्मविद्या को) आठ ब्राह्मणों को ग्रहण (स्वीकार) करवाकर तृण (जड़ी-बूटी) के द्वारा विष को मुक्त करना चाहिए। सौ ब्राह्मणों को (इसे) ग्रहण करवा करके नेत्रों से (विष को) मुक्त करना चाहिए।

क्रमशः ...

अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता दिवस

धरती के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह के रंगों के लोग पाए जाते हैं, इनमें से कुछ प्राकृतिक रूप से काले या सफेद होते हैं तो कुछ कुछ चीजों की कमी के कारण ऐसे हो जाते हैं। जो शरीर में कुछ तत्वों की कमी की वजह से बेढ़गें रंगों के हो जाते हैं उनके लिए आज 13 जून को रंगहीनता दिवस मनाया जाता है।

लैटिन ऐल्बस, सफ़ेद से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसे ऐक्रोमिया, ऐक्रोमेसिया, या ऐक्रोमेटोसिस (वर्णांधता या अवर्णता) भी कहा जाता है) मेलेनिन के उत्पादन में शामिल एंजाइम के अभाव या दोष की वजह से त्वचा, बाल और आँखों में रंजक या रंग के सम्पूर्ण या आंशिक अभाव द्वारा चिह्नित किया जाने वाला एक जन्मजात विकार है। ऐल्बिनिज़्म, वंशानुगत तरीके से रिसेसिव जीन एलील्स को प्राप्त करने के परिणामस्वरूप होता है और यह मानव सहित सभी रीढ़धारियों को प्रभावित करता है। ऐल्बिनिज़्म से प्रभावित जीवधारियों के लिए सबसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द रजकहीन जीव (एल्बिनो) है। ऐल्बिनिज़्म कई दृष्टि दोषों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे फोटोफोबिया (प्रकाश की असहनीयता), और ऐस्टिगमैटिज्म (साफ दिखाई न देना) त्वचा रंजकता के अभाव में जीवधारियों में धूप से झुलसने और त्वचा कैंसर होने का खतरा अधिक होता है।

ऐल्बिनिज़्म से पीड़ित लोगों में अकेलापन एक आम स्थिति है। अक्सर ऐसे लोगों के साथ समाज में ख़राब व्यवहार किया जाता है जिन्हें आमतौर पर ऐल्बिनिज़्म के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। लेकिन ऐल्बिनिज़्म वाले लोग अपनी ज़िंदगी में काफी कामयाब होते हैं। ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध लोगों में शामिल हैं, गौरव जैन (इंडियन आइडल फाइनलिस्ट) और प्रशांत नाइक जिन्हें बैंकिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2013 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा रोल मॉडल ऑफ द ईयर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी त्वचा और आपके बालों को रंग कहां से मिलता है? मेलेनिन नामक एक पिगमेंट, जिसका प्राथमिक कार्य सनस्क्रीन की तरह हानिकारक यूवी विकिरण से आपकी त्वचा की रक्षा करना है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में, यह महत्वपूर्ण मेलेनिन बहुत कम होता है और यह एक जेनेटिक स्थिति का कारण बनता है जिसे ऐल्बनिज़्म कहा जाता है। हर साल 13 जून को, दुनिया में ऐल्बिनिज़्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। जिसका मकसद इस समस्या पर लोगों का ध्यान केंद्रित करने और इसके प्रति लोगों को जागरुक करना होता है।

यह एक प्रकर की बीमारी है जिसमे त्वचा पर पिगमेंट की कमी हो जाती है। यह एक ऐसी बीमारी है जो इंसान, जानवर और पेड़ - पौधे किसी को भी हो सकती है। अल्बिनो की वजह से त्वचा का रंग हल्का हो जाता है। अल्बिनो को समझने से पहले आपको मेलेनिन के बारे में समझना पड़ेगा। मेलेनिन एक प्रकार का पदार्थ है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। मेलेनिन की कितनी मात्रा हमारे त्वचा में मौजूद है। इसी आधार पर हमरी त्वचा के रंग का निर्धारण होता है।

क्या मोदी को हटाने की साजिश कर रहा है अमरीका?

अजय सेठिया

राहुल गांधी के बारे में वाशिंगटन से आई इस खबर ने सबको चौंका दिया कि व्हाईट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए जाने रात्रिभोज से पहले राहुल गांधी को चाय पर बुलाया गया था। व्हाईट हाउस कोई पब्लिक गार्डन नहीं है कि जहां कोई भी कभी भी घूम आए, पहले से निर्धारित मुलाक़ात के बिना कोई व्हाईट हाउस की सीढियां नहीं चढ़ सकता। टाईम्स ऑफ इंडिया में छपी सीमा सिरोही की रिपोर्ट के मुताबिक़ राहुल गांधी ने अमेरिका के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से गोपनीय मुलाकातें कीं, जिनमे अमेरिका के विदेश मंत्रालय में दक्षिण एशिया डेस्क पर सहायक सचिव डॉन लू भी थे। डॉन लू को सत्ता पलटने का माहिर माना जाता है। इमरान खान उनका नाम लेकर खुलेआम कह चुके हैं कि उनका तख्ता पलटने में अमेरिका की दिलचस्पी थी, और अमेरिका ने डॉन लू को इस काम पर लगाया हुआ था। डॉन लू आजकल बांग्लादेश में भी इसी काम पर लगे हुए हैं। अमेरिका को जहां जहां सत्ता बदलनी होती है, वहां वहां डॉन लू को भेजा जाता है, वह विपक्ष के नेताओं के साथ मिल कर उन्हें मजबूत करते हैं। उन्हें हर तरह की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि अमरीका की पसंद का नेता उस देश के सबसे महत्त्वपूर्ण और ताकतवर पद पर काबिज हो सके।

चीन भी अपने राजदूतों के माध्यम से यही काम करता है। चीन ने अपने राजदूतों के माध्यम से दो दशक की मेहनत के बाद नेपाल में राजशाही को खत्म करके मार्क्सवादी पार्टी को इतना मजबूत बना दिया कि वहां अब मार्क्सवादियों के बिना कोई सरकार बन ही नहीं सकती। यह सब जानते हैं कि चीन भारत में किसी भी मजबूत सरकार को पसंद नहीं करता, इसलिए जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से चीन के राजदूतों ने गांधी परिवार के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू की हुई हैं। राहुल गांधी की चीनी राजदूत से गोपनीय मुलाक़ात का पिछले साल खुलासा हुआ था, तब कांग्रेस ने ऐसी किसी

मुलाक़ात का खंडन किया था। लेकिन भारत सरकार के दबाव में चीनी दूतावास ने ही इस मुलाक़ात की पुष्टि करके मुलाक़ात का फोटो रिलीज कर दिया था। बाद में काठमांडू में भी चीन की राजदूत ने राहुल गांधी से मुलाक़ात की थी। राहुल गांधी जब मानसरोवर यात्रा पर गए थे, तो चीन के अधिकारियों ने उनका नेपाल में स्वागत किया था। अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने घोर भारत विरोधी ब्रिटिश सांसद जेरेमी कॉर्बिन से मुलाक़ात की थी। कॉर्बीन ब्रिटेन में पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है, और बिटिश संसद में भारत के खिलाफ बोलता रहता है।

अब भी कांग्रेस ने राहुल गांधी की अमेरिकी प्रशासन के साथ हुई गोपनीय मुलाकातों का खुलासा नहीं किया। कांग्रेस की आधिकारिक वेबसाईट और यूट्यूब हेंडल राहुल गांधी की अमेरिकी गतिविधियों की पल पल की खबर दे रहा था, लेकिन 2 जून को उनकी डॉन लू से मुलाक़ात का जिक्र तक नहीं किया। जेएनयू से पढ़ी सीमा सिरोही वामपंथी विचारधारा की है, और राहुल गांधी की करीबी पत्रकार मानी जाती है। राहुल गांधी की पूरी यात्रा के दौरान वह उनके साथ रही थी। उसी ने राहुल गांधी की इन गोपनीय मुलाकातों का खुलासा कर दिया है। उसने लिखा कि कुछ आश्चर्यचकित कारणों से मीटिंग को गुप्त रखा गया, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए व्हाईट हाउस के दरवाजे बंद नहीं किए, वे बंद क्यों करते। यहां कई तरह की आशंकाएं पैदा होती हैं, क्योंकि न तो राहुल गांधी भारत में विपक्ष के आधिकारिक नेता हैं, न ही वह भारत के किसी सदन के सदस्य हैं। वह डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर भी अमेरिका नहीं गए थे। यह मुलाक़ात बहुत सारे सवाल खड़े करती है। क्या यह मुलाक़ात अमेरिकी प्रशासन की पहल पर हुई थी, या राहुल गांधी ने मुलाक़ात का आग्रह किया था? या जार्ज सोरोस ने यह मुलाक़ात तय करवाई, जिसने भारत में मोदी राज को उखाड़ फेंकने के लिए सौ करोड़ डालर खर्च करने का एलान किया हुआ है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार अमेरिका की आंख की किरकिरी बन चुकी है?

पिछले दिनों जापान में जब नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाक़ात हुई थी, तब बाइडेन ने मोदी की तारीफ़ के पुल बांधते हुए कहा था कि वह अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हैं। जब वह 22 जून को अमेरिका आएंगे, तो उन्हें उनके प्रशंसकों की भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सच यह भी है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की भूमिका से अमेरिका परेशान है। इस युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र स्टैंड लेकर अमेरिका को चुनौती दी है। जो बाइडेन एक व्यक्ति के नाते या अमेरिकी राष्ट्रपति के नाते भी मोदी के प्रशंसक हो सकते हैं, लेकिन जैसे भारत में सरकार किसी की भी हो, प्रशासन नियमों के मुताबिक़ काम करता रहता है, खासकर सरकारें बदलने से विदेश नीति में ज्यादा बदलाव नहीं आता, उसी तरह अमेरिकी प्रशासन व्यक्तिगत संबंधों को ज्यादा अहमियत नहीं देता, वह अमेरिका के हितों के हिसाब से ही काम करता है। नरेंद्र मोदी के स्टैंड से निश्चित ही अमेरिका की दादागिरी को बड़ा झटका लगा है। भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार इस तरह अमेरिका को चुनौती देने की हिम्मत की है। तो क्या अमेरिकन प्रशासन ने दूरगामी रणनीति के तहत राहुल गांधी से मुलाकातें की हैं, पहल भले ही किसी ने भी की हो। भारत अमेरिका के रिश्तों में एक अन्य मुद्दे को लेकर भी बड़ी कड़वाहट है। और वह है लोकतंत्र और विकास से जुड़े कार्यों की आड़ में अमेरिका से फंड हासिल करके भारत के विकास में अड़चने पैदा करने वाले गैर सरकारी संगठनों की घेराबंदी। मोदी सरकार ने उनकी घेराबंदी करके उन हजारों एनजीओ के एफसीआरए लाईसेंस रद्द कर दिए हैं, जो अमेरिका से फंड लेकर भारत में अमेरिकी हितों की राजनीति कर रहे थे। इस काम में अमेरिका संयुक्त राष्ट्र का भी इस्तेमाल कर रहा था।

अमेरिकी पहल पर दुनिया भर में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के नाम पर 2005 में संयुक्त राष्ट्र में एक फंड की स्थापना की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश के साथ मनमोहन सिंह इस फंड के सहायक संस्थापक बने थे। मनमोहन सरकार ने इस फंड में हर साल 5 मिलियन डालर की प्रतिबद्धता दिखाई थी। जब तक प्रधानमंत्री रहे, भेजते भी रहे। संयुक्त राष्ट्र यह फंड उन संस्थाओं को अनुदान देता था, जो तथाकथित रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करती हैं। इस फंड का काफी हिस्सा जार्ज सोरोस को भी मिलता है, जो आगे दुनिया भर के छोटे एनजीओ को बांट कर अपने व्यापार के अनुकूल सरकारें बनवाने के लिए इस्तेमाल करता है। जार्ज सोरोस की संस्था भारत में भी मोदी विरोधी संस्थाओं को फंड दे रही है। जिन संस्थाओं को जार्ज सोरोस से फंड मिलता रहा, उन्होंने 2002 से नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने में अहम भूमिका निभाई थी। यानि भारत का पैसा भारत की सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। मोदी सरकार ने न सिर्फ छंटनी करके उन सभी एनजीओ के एफसीआरए लाईसेंस रद्द किए, बल्कि संयुक्त राष्ट्र डेमोक्रेसी फंड में भारत का योगदान भी लगातार घटाते हुए अब सिर्फ 50 हजार डॉलर सालाना कर दिया है। बीच में दो साल तो भारत ने खोटी कौड़ी नहीं दी। अमेरिका भारत में किस तरह के खेल करता रहा है, इसी सन्दर्भ में राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान एक नाम भारत में जासूसी में पकड़े गए विवेक रघुवंशी का भी आया। वह अमेरिका की ही एक डिफेन्स वेबसाईट के लिए काम करता था।

बापू की दिनचर्या

दिन का भोजन (भाग-2)

जब उन्होंने उनको दूर से आते देखा तो सोचा कि उनके निकट आ जाने पर बजाऊँ। यह बात ज्ञात होने पर बापू ने उनसे भविष्य में ऐसा न करने को कहा। उनकी दृष्टि में ऐसा कर उन भाई ने दूसरे व्यक्तियों का समय नष्ट किया। बापू चाहते थे कि वे पिछड़ जाएँ तो उनका पिछड़नेवालों के साथ बाहर बैठना ही उचित है। उनके कारण घंटी में तनिक विलंब नहीं होना चाहिए। सत्याग्रह आश्रम में घंटी का आधिपत्य बापू के बाद प्रथम श्रेणी का था, ऐसा नारायण भाई का कहना बिलकुल सही है। वहाँ सुबह उठने से लेकर रात्रि के शयन तक- प्राय: हर कार्य के लिए घंटी बजती। दिनभर में गिनने पर छप्पन घंटियों की आवाज एक दिन सुनी गई। हर भोजन के समय वहाँ तीन घंटियाँ बजतीं। पहली घंटी भोजन का समय होने पर बजती, दूसरी बजने पर भोजनालय के द्वार बंद हो जाते और तीसरी बजने पर भोजनमंत्र शुरू हो जाता। आश्रम में सभी के साथ बापू भोजन करने बैठते। वे मंद गति से खाते । सब लोग भोजन कर चले जाते, किंतु वे अकेले बैठे खाते रहते। अन्यत्र भी उनकी इस गति में कोई अंतर नहीं आता। उनको आहार ग्रहण करने में साधारणत- एक घंटा लगता। न खाने से वे उतनी हानि नहीं मानते, जितनी बिना ठीक से चबाए आहार से। वृद्धावस्था में भोजन भली-भाँति चबा सकने के लिए वे नकली दाँतों का उपयोग करते। आहार मुँह में रखकर वे उसको कुचलते और तरल बनाकर निगलते। वे आहार खाते नहीं, बल्कि पीते, यहाँ तक कि दही को भी खूब घुलाकर निगलते। उनके कथनानुसार ऐसा कर थोड़े आहार से भी पर्याप्त सत्त्व ग्रहण किया जा सकता है। आश्रम में देशी-विदेशी पर्यटक, अतिथि, नेता, जिज्ञासु - सभी से अपने साथ, अपने निकट बैठने का बापू आग्रह करते। वे उनकी थाली स्वयं परोसते। किसी पर अत्यंत कृपालु हो जाते तो अपने खाने की वस्तुओं में से उसे कुछ दिया करते। उस व्यक्ति की विशेष प्रिय वस्तु उसे खिलाने का भी उनका प्रयत्न रहता। भोजन-संबंधी अपने विविध प्रयोगों की जानकारी बापू अतिथियों को देते जाते। कहते- इस खाखरे में एक चम्मच सोडा डाला गया है और यह चटनी किस चीज की है, जानते हो? खाओगे, तब पता चलेगा। कड़वे नीम का कड़ुवापन तो उसका गुण ही है न? लहसुन रक्तचाप के लिए लाभदायक है। सेवाग्राम में दो कतारों में बैठे आश्रमवासियों को पहले बापू परोसा करते। उन दिनों लोग भोजन बनाकर उनके सामने रख देते और अपने- अपने बर्त्तन उनके पास ले जाते। बाद में कुछ असुविधा तथा अस्वस्थ हो जाने से वे मीरा बहन की कुटी में रहने लगे।

क्रमशः ..

जनता की मूलभूत सुविधाओं में भागीदार बनेंगे 'जल मितान'

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल मितान-युवा उद्यमी उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में जल-जीवन मिशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में जल मितान-युवा उद्यमी उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम की आज शुरुआत की। इस दौरान सीएम और गुरु रुद्रगुरु सहित अतिथियों ने कार्यक्रम में 90 जल मितान एवं युवा उद्यमियों को टूल किट बांटे। टूल किट में युवाओं को सुरक्षा जूता, हेलमेट आदि दिए गए।

सीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन से हर घर में जल आपूर्ति की विकसित की जा रही है। अधोसंरचना के स्थायी रखरखाव के लिए राज्य के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर जल मितान और युवा उद्यमी के रूप में तैयार किया गया है। जल जीवन मिशन एवं यूनिसेफ की भागीदारी से पेयजल आपूर्ति की निर्मित अधोसंरचना के स्थाई रखरखाव के लिए राज्य के 540 युवाओं तथा 90 युवा उद्यमियों को 21 दिनों की आवासीय ट्रेनिंग दी गई है। युवाओं को प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, सोलर पैनल रिपेयरिंग, आर.ओ. रिपेयरिंग आदि की ट्रेनिंग दी गई है।

बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जल मितान, युवा उद्यमी तथा जल दीदी के रूप में उन्हें योजनाओं के संधारण और संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के साथ कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 540 युवाओं को उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें आज निशुल्क टूल किट प्रदान किया गया। इन प्रशिक्षित जल मितान और जल दीदियों को स्वरोजगार के नए अवसर मिले हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण प्राप्त सभी युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

50 लाख घरों में नल जल कनेक्शन देने का लक्ष्य

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के 50 लाख घरों में नल जल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत अब तक 24 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जब इतनी बड़ी संख्या में नल कनेक्शन दिए गए हैं तो उनके संचालन और संधारण के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत भी है, ताकि योजनाओं का सुचारू संचालन हो सके। इन प्रशिक्षित युवाओं को हमेशा रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे। काम की कमी नहीं होगी। हाल में कोंडागांव के प्रवास के दौरान भी वहां कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त करीब 550 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए थे। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य निरंतर किया जा रहा है

जल मितान की सेवाएं

जल मितान जल गुणवत्ता परीक्षण सर्विसेज, नल व पाइप फिटिंग रिपेयरिंग, आरो फिटिंग/ रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग /रिपेयरिंग , सोलर पैनल फिटिंग/रिपेयरिंग, पम्प आपरेटर की सेवाएं देंगे।

संक्षिप्त समाचार

चुनाव तक पद पर बने रह सकते हैं डीजीपी जुनेजा

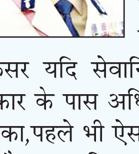

रायपुर। विधानसभा चुनाव में बमुश्किल पांच माह बचे हैं ऐसे में सीनियर अफसरों की जरूरत राज्य सरकार को रहती है जिनके कार्यअनुभव से व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके ऐसे मे कोई सीनियर अफसर यदि सेवानिवृत होने को हैं तो राज्य सरकार के पास अधिकार होता है उन्हे सेवावृद्धि देने का,पहले भी ऐसा हुआ है। फिलहाल बात हो रही है राज्य पुलिस प्रमुख अशोक जुनेजा की,जो कि 30 जून को सेवानिवृत हो रहे हैं। सरकार ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जायेगा। उन्ही की अगुवाई में ही चुनाव संपन्न कराया जायेगा। हालांकि शासकीय तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है।

नवनियुक्त कलेक्टर मलिक ने कार्यभार ग्रहण किया

महासमुंद। जिले के नवनियुक्त कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने आज सोमवार को कार्यभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने निर्वाचन शाखा के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन सुरक्षा का जायजा लिया। श्री मलिक जिला गरियाबंद से स्थानांतरित होकर यहां आए हैं। श्री मलिक भारतीय प्रशासनिक सेवा वर्ष 2015 बैच के अधिकारी हैं। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री दुर्गेश कुमार वर्मा, एसडीएम श्री उमेश साहू, डिप्टी कलेक्टर एवं जिला उप निर्वाचन अधिकारी श्रीमती ऋृु हेमनानी, डिप्टी कलेक्टर श्री श्रवण कुमार टंडन, सुश्री नेहा भेडिया, श्रीमती मिषा कोसले, वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी श्री डी.पी. वर्मा एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया।

एथेनाल प्लांट लगाने दे दी एनओसी, संडी के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में

एथेनाल प्लांट का जमकर विरोध हो रहा है। आज इसी क्रम में आरंग के ग्राम संडी से करीब 300 से अधिक किसान और ग्रामीण रायपुर कूच किए। यहां के कलेक्ट्रेट आफिस में पहुंचकर जमकर विरोध प्रदशर्न किया। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर बड़ा प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि इस मामले में राज्य सरकार तुरंत कार्रवाई करें। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो आगे और भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम पंचायत संडी की ओर से फर्जी ग्राम सभा कर एनओसी दिया गया है, जिसका वे घोर विरोध करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अनुमति रद्द करने की मांग की। ग्रामीण और किसान प्रदूषण की आशंका को लेकर एथेनाल प्लांट का भारी विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में तपती धूप में हाथों में तख्ती और बैनर-पोस्टर लेकर ग्रामीण रायपुर कलेक्टोरेट पहुंचे। मामले में प्रदर्शन कर विरोध जताया।

समर वेकेशन खत्म, हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू

बिलासपुर। समर वेकेशन खत्म होने के बाद अब हाईकोर्ट में आज सोमवार 12 जून से सभी बेंचों में नियमित सुनवाई शुरू की जा रही है। अवकाश बाद अब नियमित बेंच में महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े मामलों के अलावा अन्य लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। हाईकोर्ट में मई के दूसरे सप्ताह के खत्म होते ही समर वेकेशन शुरू हो गया था। इस बीच लगातार चार सप्ताह तक यहां अवकाश रहा। इस दौरान हर सप्ताह वेकेशन जजों ने मामलों की सुनवाई की। इनमें अर्जेंट प्रकृति के मामले प्रमुख तौर पर सुने गए। सोमवार और गुरुवार को वेकेशन बेंच में जरूरी मामलों की सुनवाई वेकेशन के दौरान की गई। चीफ जस्टिस के निर्देश पर इस बार सिंगल बेंच के अलावा डिवीजन बेंच भी अवकाश में बैठी। अवकाश के दौरान भी कई महत्वपूर्ण मामलों में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण व जनहित याचिकाएं भी शामिल थीं। चीफ जस्टिस ने डिवीजन व सिंगल बेंच के अलावा 6 स्पेशल सिंगल बेंच भी निर्धारित की गई हैं। उनमें एक कैलेंडर ईयर को ध्यान में रखते हुए मामलों की सुनवाई तय की गई है। जिस साल के लंबित मामलों की संख्या ज्यादा है, उस वर्ष के मामले जल्द निपटाने के लिए स्पेशल बेंच बनाई गई है।

तीन दिवसीय प्रवास पर कल आएंगी राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन

रायपुर। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन मंगलवार को शाम 5.10 बजे इंडिगो के नियमित विमान सेवा द्वारा नई दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगी एवं रात्रि विश्राम रायपुर में करेगी। 14 जून को दोपहर 1 बजे सीमेंट कांक्रीट रोड के उद्घाटन एवं भिलाई में अमित पार्क इंटरनेशनल होटल में एमपीएलएडी (फंड कार्यक्रम में भाग लेंगी। दोपहर 2 बजे भिलाई के लाल बाहदुर शास्त्री हास्पिटल भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगी। दोपहर 3 बजे अमित पार्क इंटरनेशनल होटल में जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी।

सर्व आदिवासी समाज 21 जून से करेगा धरना-प्रदर्शन

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज अब आरक्षण को लेकर आंदोलन की राह पर है। पांचवीं अनुसूचि में स्थानीय आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर 21 जून से बस्तर संभाग के सभी जिलों में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। समाज ने मांग पूरी नहीं होने पर आर्थिक नाकाबंदी की चेतावनी दी है। इसे लेकर सोमवार को तेतरखूटी वन विद्यालय के पास हुई बैठक में आदिवासी बाहुल्य (5वीं अनुसूची) क्षेत्रों मे स्थानीय आरक्षण बहाल करने, स्थानीय आधार पर भर्ती, अनुसूचित क्षेत्रों मे गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन के लीज के संबंध मे पेशा अधिनियम 2022 के संशोधन और अन्य विषयों पर चर्चा की गई।

संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने बताया कि, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में स्थानीय आरक्षण बहाल को लेकर 21 जून को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन पर रैली के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया जाएगा मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकाबंदी की जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन को लीज के सम्बंध में पेसा अधिनियम 2022 के संशोधन को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा कर संशोधन करने की राज्य सरकार को मांग रखेंगे। स्थानीय आरक्षण बहाल की मांग पर सभी को एक साथ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग प्रदेश अध्यक्ष सुभाष परते ने बताया कि राज्य की पूर्व और वर्तमान सरकार ने आदिवासी समुदाय को शोषण करने का कार्य किया है। आदिवासी समाज ने हमेशा जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी है। समाज की ताकत के कारण 32 प्रतिशत आरक्षण की लड़ाई लड़ी और उसे हासिल किया। इसी तर्ज पर वर्तमान में स्थानीय आरक्षण बहाल को लेकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है।

शराब घोटाले में ईडी की एक और गिरफ्तारी

अरविंद सिंह हिरासत में, मां के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा था मुक्तिधाम

भिलाई। छत्तीसगढ़ में कथित दो हजार करोड़ के शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने सोमवार को ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले टीम पूछताछ के आधार पर लगातार उनकी तलाश कर रही थी। इस बीच पता चला कि अरविंद सिंह अपनी मां के अंतिम संस्कार में मुक्तिधाम पहुंचा है। ईडी ने वहीं से उसे पकड़ लिया। ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह को ईडी की गिरफ्त में आए आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुण पति का करीबी बताया जा रहा है।

शराब कारोबारी से पूछताछ के बाद कार्रवाई

दरअसल, प्रदेश में शराब घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। इससे पहले पुलिस ने दुर्ग से शराब कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि उससे हुई पूछताछ के आधार पर ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह भी ईडी की रडार पर आ गया। अरविंद सिंह की भी तलाश शुरू की गई, लेकिन वह फरार हो गया। अरविंद सिंह की मां कलावती देवी का रविवार को निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अरविंद भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम पहुंचा था।

अरुण पति का बताया करीबी

भिलाई के खुर्सीपार निवासी अरविंद सिंह के मुक्तिधाम पहुंचने की सूचना पर ईडी ने भी वहां घेराबंदी कर दी। अंतिम संस्कार की विधि पूरी होते ही ईडी ने अरविंद को हिरासत में ले लिया और टीम उसे लेकर अपने साथ चली गई। इस दौरान वहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय, विधायक देवेंद्र यादव सहित तमाम लोग मौजूद थे। ईडी ने इससे पहले पिछले महीने आबकारी विभाग के सचिव अरुण पति त्रिपाठी को मुंबई से गिरफ्तार किया था। अरविंद सिंह को उनका ही करीबी बताया जा रहा है।

ईडी ने शराब सिंडिकेट चलाने का किया है दावा

इससे पहले ईडी ने दावा किया कि आईएएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर अवैध रूप से शराब सिंडिकेट चला रहे थे। दोनों उस सिंडिकेट के सरगना थे। जांच में यह भी पता चला है कि 2019 से 2022 तक, राज्य में कुल शराब बिक्री में करीब 30 से 40 प्रतिशत अवैध रूप से की गई। भ्रष्टावार की रकम का इस्तेमाल चुनाव में प्रचार में किया गया। शराब कारोबारी अनवर ढेबर को ईडी ने छह मई को गिरफ्तार किया था। कारोबारी अनवर ढेबर कांग्रेस नेता और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के बड़े भाई हैं।

अनवर के कहने पर राज्य विपणन निगम का प्रबंध निदेशक बना

ईडी ने कहा था कि, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड को अपने स्टोरों के माध्यम से राज्य में शराब की खुदरा बिक्री की जिम्मेदारी दी गई। मई 2019 में, अनवर के कहने पर अरुणपति त्रिपाठी को छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया था। इसके बाद त्रिपाठी को छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड की ओर से खरीदी गई शराब पर वसूले जाने वाले रिश्वत कमीशन को अधिकतम करने और निगम की संचालित दुकानों में गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब की बिक्री के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का काम सौंपा गया।

खाद्य मंत्री ने 100 से अधिक हितग्राहियों को दी 14.55 लाख रूपए की सहायता राशि

रायपुर। खाद्य और संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत ने सीतापुर और बतौली विकासखंड के 100 से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत् 14 लाख 55 हजार रूपए की सहायता राशि वितरित की। उन्होंने बंशीपुर - राताखांड होते हुए दमगड़ा मुख्य मार्ग से अंदरूनी गांव के लिए लगभग 8 किमी लंबाई की सड़क एवं पुल-पुलिया की स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री भगत ने असंगठित कर्मकार दिव्यांग सहायता योजना अंतर्गत जिन हितग्राहियों को चेक वितरित की उनमें शांति दास को एक लाख रुपए, घरेलू महिला कामगार योजना अंतर्गत 16 हितग्राहियों को 3 लाख 20 हज़ार रुपए, स्वेच्छा अनुदान से 52 हितग्राहियो को 4 लाख 90 हज़ार रुपए शामिल हैं। इसी प्रकार श्री भगत ने सीतापुर के हितग्राहियों को श्रम विभाग के अंतर्गत दिव्यांग सहायता योजना की हितग्राही पिंकी को 1 लाख रुपए, घरेलू कामगार योजना और प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत 16 पात्र हितग्राहियों को 3 लाख 20 हज़ार रुपए, इस दौरान श्री भगत ने स्वेच्छानुदान से 20 हितग्राहियों को 1 लाख 25 हज़ार का सहायता राशि जरूरतमंदो को प्रदान की।

कांग्रेस जनता को लूट रही : बृजमोहन अग्रवाल

पूर्व मंत्री बोले- भूपेश नहीं ठगेश है, कांग्रेस 15 साल से नंगी-भूखी

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बार फिर राजनीतिक जोर आजमाइश शुरू हो गई है। इस दौरान आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ऐसे में नेताओं की जबान से बिगड़े बोल निकल रहे हैं। अब प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ठग बता दिया है। साथ ही यह भी कहा कि 15 सालों से कांग्रेस प्रदेश में नंगी-भूखी थी। अब जनता को लूटने का काम का रही है। पूर्व मंत्री अग्रवाल भाटापारा में हो रही भाजपा की आम सभा में बोल रहे थे।

भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, गरीबों के 550 करोड़ का धान ये सरकार खा गई। उन्होंने कहा कि, मोदी सरकार ने सिर्फ वैक्सीन ही नहीं दी, बल्कि गरीब कल्याण के लिए चार साल के लिए एक व्यक्ति को पांच किलो चावल दिए। यह चावल लोगों को मिला ही नहीं। इसे कौन खा गया? इसका बदला लेना है। कहा कि, बोलने के लिए बहुत कुछ है, अगर ज्यादा कुछ बोलूंगा तो उनका सब कपड़ा उतर जाएगा। गौठानों की हालत छिपी नहीं है। कांग्रेसियों से ही गोबर खरीद रहे हो, क्या सिर्फ कांग्रेसी गोबर दे रहे हैं?

पूर्व मंत्री ने कहा कि, इनके पास केवल एक ही काम है। 15 साल तक भूखा-नंगा रहे, ऐसे में जनता को जितना लूट सकते हो, लूट लो। उसके बाद मौका मिलेगा या नहीं। उनको भी समझ में आ गया है कि आने वाले नवंबर में चुनाव होगा तो भाजपा की सरकार बनेगी। कहा कि, जनता को भी लगता है कि, यह भूपेश नहीं है, ठगेश है। हमको भी समझ में आ गया है। बदलना है इस बार। अटल जी के बनाए इस राज्य में फिर भाजपा को जितना है। कहा कि, हाथ का पंजा उठाकर नहीं, बजरंगबली की तरह मुठ्ठी बनाकर बताओ।

उड़ान पर रार, अरुण साव को तो धरने पर बैठ जाना चाहिए : भूपेश बघेल

■ **भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा राज्य सरकार का सहयोग नहीं**

रायपुर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आने वाली एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया एएआइ ने उड़ान 5.0 योजना से लाभान्वित एयरपोर्ट की सूची से बिलासपुर और जगदलपुर का नाम हटा दिया है। इसके बाद से लगातार राजनीति जारी है। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है वहीं भाजपा अध्यक्ष व बिलासपुर के सांसद अरूण साव पर तंज कसा है देखिए अध्यक्ष जी आपकी सरकार आपकी बात नहीं सुन रही, इस उपेक्षा के लिए आप जनता को साथ लेकर विरोध दर्ज करायें, आखिर बिलासपुर व छत्तीसगढ के साथ भेदभाव क्यों?

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उड़ान योजना बंद कर दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साव को अपने लोकसभा क्षेत्र में जाना चाहिए। साव अपने लोकसभा क्षेत्र में उड़ान योजना शुरू कराएं। उनको तो उड़ान शुरू कराने के लिए धरने पर बैठ जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने तंज कसा कि क्या साव की

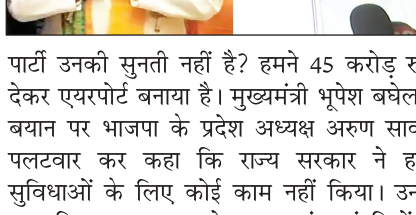

पार्टी उनकी सुनती नहीं है? हमने 45 करोड़ रुपये देकर एयरपोर्ट बनाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार कर कहा कि राज्य सरकार ने हवाई सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एयर लाइंस कंपनियों को सहयोग नहीं किया इसलिए वह छोड़कर भाग रहे हैं। गौरतलब है कि इस हवाई सुविधा के लिए प्रदेश जन संघर्ष समिति ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को पत्र लिखकर बिलासपुर एयरपोर्ट को उड़ान 5.0 योजना में शामिल करने की मांग की थी। इसके अलावा राज्य के राज्यपाल से भी मिलकर समिति ने इस सुविधा को शुरू करने की मांग की है।

नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

कवर्धा। पांडातराई नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। तीन साल में दूसरी बार पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला है।कांग्रेसी पार्षद नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान की कुर्सी गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। पिछली बार अध्यक्ष ने अपने सूझबूझ और सत्ताधारी पार्टी होने के कारण अपनी कुर्सी बचा ली थी। लेकिन 15 महीने बाद एक बार फिर पार्षदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर को सौंपा है।

पहले भी हो चुकी है शिकायत

नगर पंचायत पांडातराई के कांग्रेसी अध्यक्ष फिरोज खान को हाटाने की मांग को लेकर 05 कांग्रेसी और 04 भाजपा के पार्षद एक होकर 15 महीने पूर्व कलेक्टर को आवेदन दिए थे। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेकर वोटिंग भी कराया। लेकिन अध्यक्ष फिरोज खान के समर्थन

में वोट ज्यादा पड़े और उनकी कुर्सी बच गई। कांग्रेस के पार्षदों ने ही पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लगाया था।जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नीलकंठ चन्द्रवंशी ने पांचों पार्षदों को पार्टी से 06 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन अब फिर से कांग्रेस निष्कासित पार्षद और बीजेपी पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला है।

क्यों लाया गया अविश्वास प्रस्ताव

पार्षद जसबीर सलूजा ने आरोप लगते हुए कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान ने प्रधानमंत्री आवास में अपने चहेतों को योजना लाभ दिलाया है। वहीं सड़क निर्माण में अनियमितता और भ्रष्टाचार किया है। पार्षदों से भेदभाव करना जैसे कार्य लगातार करते आ रहे हैं। जिन पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है उनमें संतोष गेंदले, जसबीर सलूजा, तीजन बाई,सविता पातस्कर, जानकी बाई बाहिरे, सोनमत बाई साहू, राजकुमारी चन्द्रवंशी, फूलचंद साहू, दिनेश गुप्ता शामिल हैं।व हीं इस पूरे मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष ने इसे खुद के खिलाफ षड़यंत्र बताते हुए जनता को अपने साथ बताया है।वहीं कलेक्टर जनमेजय महोबे ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का होगा सफाया : रमन

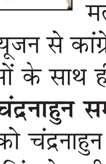

कवर्धा। क्रिकेट के मैदान पर भिड़ने से पर पहले धुर प्रतिद्वंद्वी माइंड गेम खेलते हुए एक दूसरे को कमजोर बताने की कोशिश करते हैं, ताकि अगले की रणनीति को कमजोर किया जा सके। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार पर घपले घोटाले का आरोप लगाने और भागवान राम के नाम पर घेरने के बाद अब भाजपा भी माइंड गेम खेलने पर उतर चुकी है। हर मोर्चे पर बघेल सरकार को कमजोर दिखाकर मतदाताओं को कन्फ्यूज करने की कोशिश हो रही है। इसी कन्फ्यूजन से कांग्रेसी वोट बैंक में सेंध लगाने की योजना है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेताओं के साथ ही केंद्र से आने वाला हर नेता अब इसी रणनीति पर चल रहा है।

चंद्रनाहुन समाज के कार्यक्रम में रमन ने किया ये दावा- कवर्धा में 10 जून को चंद्रनाहुन कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक सम्मेलन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सफाया होने का दावा किया। भूपेश सरकार पर हमला करते हुए रमन सिंह ने कहा कि ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनका काम छत्तीसगढ़ के विकास में बाधा पहुंचाना है। इसलिए भूपेश बघेल को धोखे में नहीं रहना चाहिए।

भाजपा के पास है केवल 14 सीटें- छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस के पास 71 तो भारतीय जनता पार्टी के पास 14 सीट है। बाकी की 5 सीटों में से 3 जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) और दो सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस 75 से अधिक सीटें लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस का भ्रम करार दिया है।

1500 लोगों ने थामा बीजेपी का दामन

धमतरी, राजिम, महासमुंद में प्रभारी ओम माथुर ने कराया प्रवेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रदेश में पार्टी को लगातार मजबूत करने में लगे हुए हैं। इस क्रम में आज सोमवार को उन्होंने धमतरी, राजिम, महासमुंद आदि का दौरा किया। महासंपर्क अभियान के दौरान करीब 1500 लोगों ने बीजेपी की रीति-नीति से प्रभावित होकर पार्टी में प्रवेश किया। ओम माथुर की मौजूदगी में लोगों ने बीजेपी का दामन थामा।

इस दौरान धमतरी, राजिम, महासमुंद में कांग्रेस और जनता कांग्रेस के नेताओं सहित लगभग 15 सौ लोगों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद चुन्नीलाल साहू, कुरुद विधायक अजय चंद्राकर, धमतरी विधायक रंजना साहू, शशि पवार की मौजूदगी में भाजपा में प्रवेश किया। इनमें गायत्री परिवार के समाजसेवी, आदित्य युवा वाहिनी, कांग्रेस पदाधिकारी, पूर्व अधिकारी और नव मतदाता शामिल हैं।धमतरी में प्रदेश भाजपा प्रभारी ओम माथुर ने लाभार्थी सम्मेलन में केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों का सम्मान किया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश शर्मा सहित करीब एक हजार लोगों ने भाजपा प्रवेश किया। माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भाजपा का गमछा पहनाकर नव प्रवेशी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। राजिम में माथुर और साव ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाए। इस अवसर पर 50 लोगों ने भाजपा प्रवेश किया। इनमें जोगी कांग्रेस युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश साहू, पूर्व नगर अध्यक्ष राजिम युवक कांग्रेस सोमू साहू, रिटायर्ड रेंजर ललित सिन्हा भी शामिल हैं। महासमुंद की सभा में कांग्रेस पार्षद राजेन्द्र राजू चंद्राकर, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर सहित 80 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया।

सोमवार को बड़े पैमाने पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन धमतरी पुरानी मंडी में किया गया। जहां केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले तीन हजार से अधिक लाभार्थियों का सम्मान किया गया। लाभार्थी सम्मेलन में छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी ओम माथुर एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव,पूर्व मंत्री कुरूद विधायक अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, रायपुर संभाग प्रभारी अकलतरा विधायक सौरभ सिंह, सांसद चुन्नीलाल साहू, विधायक रंजना साहू, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, भाजपा नेता छत्तीसगढ़ी स्टार अनुज शर्मा, धमतरी जिला प्रभारी नीलू शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए। विभिन्न क्षेत्रों से 1500 से अधिक लोगों ने प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में भाजपा का दामन थामा, जिसमें प्रमुख रूप से धमतरी के जाने माने समाजसेवी पूर्व कांग्रेस नेता पंडित राजेश शर्मा, महिला कांग्रेस प्रदेश नेता ईश्वरी पटवा, प्रोफेसर चंद्रशेखर चौबे, एच पी सिन्हा, डी पी भार्गव, पी वी पराड़कर, गौरीशंकर दुबे, राजकुमार शर्मा, चंद्रिका साहू, निखिल अग्रवाल, चंदू जैसवानी, विकास शर्मा आदि शामिल हैं। माथुर ने कहा कि 62 साल तक इस देश में एक परिवार और एक दल ने राज किया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार आई जिसने लोकतंत्र को सही मायने में परिभाषा दी। पहले सत्ता को अपने लाभ के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन अब देश की उन्नति व देशवासियों की भलाई के लिए सत्ता माध्यम बन रही है। देश-दुनिया में भारत का मान मोदी ने बढ़ाया। प्रत्येक व्यक्ति को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है।

इससे पूर्व सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष साव ने एक ओर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र, एक सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों की चर्चा की तो दूसरी ओर प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिनाई। साव ने कहा कि हर व्यक्ति के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का कोई-न-कोई लाभ पहुंचा है। भूपेश सरकार को लबरा सरकार बताते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने जो जनता से वादा किया था, उन्हें पूरा नहीं किया। और तो और केंद्र सरकार की योजनाओं को भी रोक कर रख दिया। राज्य के विकास में भूपेश बघेल सबसे बड़ा रोड़ा हैं। शराबबंदी, बिजली बिल हाफ जैसे तमाम झूठे वादे कर कांग्रेस सत्ता में आई थी पर अब जनता सच जान चुकी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि ये कांग्रेस सरकार जाने की बेला में है। धमतरी के कांग्रेसी नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि धमतरी और पूरा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के भूकंप का केंद्र बना हुआ है, और कांग्रेसी कोष-प्रमुख लापता हैं। हर प्रकार की वसूली और माफियागिरी में कांग्रेस सरकार पूरी तरह संलिप्त है।

मेरी बात

✍ गिरीश पंकज

'नदी' को 'दीन' होने से बचाएँ !

नदी को एक कूड़ादान तो हमने बनाया है .
प्रदूषित जल, प्रदूषित मन भी हमने ही मिलाया है
'नदी' को 'दीन' करने का किया है पाप मानव ने.
हमीं ने इस सुधा में आके कितना विष मिलाया है

कभी कभी नदियों की दुर्दशा पर कुछ मुक्तक लिखे थे। यह मुक्तक आज फिर मनेंद्रगढ़ प्रवास के दौरान याद आया, क्योंकि यहाँ जीवनदायिनी हँसिया नदी संकट से जूझ रही है। इसे बचाने और पहले जैसी भरीपूरी बनाने की दिशा में अब संस्था ग्रीन वैली नामक संस्था और पतंजलि योग समिति के सदस्य शहर के लोगों का सहयोग लेकर निरन्तर श्रमदान कर रहे है। हसदो और विशालबोरा नदी भी सूख रही है, जिस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। गनीमत है कि केवई नदी अभी सुरक्षित है। रायपुर की खारुन नदी और बिलासपुर की अरपा को लेकर लोग सेवाकार्य करते रहे हैं। तालाबों की साफ-सफाई भी जन सहयोग से हो रही है। मनेंद्रगढ़ जैसे अनेक शहरों में कुछ बड़े तालाब रहे हैं। जो पाट दिए गए, वहाँ दुकानें तन गईं। कुछ लापरवाही के कारण सूख गए या जलकुंभी से पट चुके हैं। बस कुछ ही शेष हैं। यह एक शहर की बात नहीं। अनेक शहरों में तालाबों को पाट कर व्यावसायिक या मनोरंजन परिसर बनाने की नादानी हो रही है। हम देश का इतिहास देखें तो जल संरक्षण की दिशा में हमारा देश सदियों पहले बहुत गम्भीर रहा है. राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ अथवा अन्य कोई राज्य, लगभग हर जगह बड़े-बड़े तालाब बनाए जाते थे, बड़े-बड़े कुएँ-तालाब आज भी हमे दंग कर देते हैं, खास कर राजस्थान में जल संरक्षण की परम्परा रही क्योंकि यहाँ लोगों को जल -संकट का आभास था, इसलिए उसका विकल्प भी उन्होंने विकसित कर लिया था. पर अब इस दिशा में न तो गाँव के लोग गम्भीर हो कर सोच रहे हैं, और सरकारें भी। औद्योगीकरण के कारण गाँव पहले जैसे नहीं रहे.वहां उद्योगजनितप्रदूषण का विस्तार हुआ है। उस पानी की निकासी के लिए अलग नाली बननी चाहिए। हँसिया नदी को भी प्रदूषण से बचाने के लिए यही सुझाव सामने आया। कभी हँसिया नदी दो सौ फुट तक चौड़ी थी, अब सिमट कर सत्तर फुट हो गई। लोगों ने नदी के किनारे घर बना लिए। इसके कारण नदी सिमटती गई, सूखती गई। लेकिन अब लोग जागरुक हुए है, जब बहुत देर हो चुकी है। फिर भी कोशिश हो रही है कि नदी प्रदूषण मुक्त हो सके। जब देश मुगलों के अधीन था, तब गाँव का तंत्र गाँव के अधीन ही रहता था, गुलाम था,हमने नदियों की पूजा की, उनको पवित्र कहा। सैकड़ो श्लोक रचे गए नदियों की वंदना में. आज भी अनेक नदियां पवित्रता की प्रतीक हैं. गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा आदि अनेक नदियों को हम पूजते रहे हैं पर आज ये ही नदिया किस हाल में हैं, किसी से छिपा नहीं है. हालत यह है कि कभी भीषण जल संकट के समय कुछ शहरों में ट्रेनों के जरिये पानी पहुंचाया गया. यह कितनी भयावह स्थिति है कि हम अपनी जीवनदायिनी नदियों को सूखने पर विवश कर देते हैं। मनुष्य की उदासीनता, उसकी अज्ञानता ही उसके विनाश का कारण बनती जा रही है. जंगलों में आग लगने का सिंलसिला भी सामने है. आग लगाने वाले लोग ही है. उत्तराखंड में कुछ लोग गिरफ्तार किये गए हैं. नदियों को प्रदूषित करने वाले भी दण्डित किये जाने चाहिए। मतलब यह कि अपने कुछ स्वार्थ के लिए हम अपने जंगल और

अपनी नदियों की जान भी ले सकते हैं. गंगा जो आज प्रदूषित है, उसके पीछे बड़ा कारण औद्योगिक प्रदूषण तो है ही, वे लोग भी जिम्मेदार है, जो नित गंगा का इस्तेमाल करते हैं. जितना नहाते नहीं, उससे ज्यादा उसे गंदा करके लौटते हैं. इसलिए अब जरूरी है कि नदियों के किनारे जल सैनिक तैयार किये जाएँ।

सीमा पर सैनिक तैनात रहते हैं देश की सुरक्षा के लिए जवान तैनात रहते हैं,. उसी तरह अब नदियों को बचाने के लिए जवानों को तैनात करने की नौबत आ चुकी है. पता नहीं क्यों लोग नदियों का समुचित संरक्षण नहीं कर पाते। प्रदूषण इतना है कि उनका आचमन तक करने में डर लगता है. एक सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र की नदिया सर्वाधिक प्रदूषित है, उसके बाद गुजरात और फिर उत्तरप्रदेश की नंबर आता है. आश्चर्य है कि लोग नदियों को पूजते तो हैं पर उसे बचाने के लिए व्याकुल क्यों नहीं होते? पानी अभी सहजता से उपलब्ध हो जाता है इसलिए शायद मन में उसकी भीषण कमी की कल्पना नहीं कर पाते। लेकिन उनको कल्पना करनी होगी और नदी के जल को अँजुरी में भर कर संकल्प लेना होगा कि ये हमारी माँ है, इसे हम बचाएंगे, इसे गन्दा नहीं करेंगे। नदी को प्रदूषण मुक्त करना हमारा प्रथम कर्तव्य है. इन नदियों के प्रति जागरूक करने का काम जल कल्याण परिषद जैसी संस्थाएं कर सकती हैं। जल गीत लिखें जाएँ, नाटक मंचित हो, कहानिया लिखी जाए, जल पर निरन्तर विमर्श हो. नदियों के तात पर नदी महोत्सव हो, पर यह भी ध्यान रहे कि महोत्सव नदियों के प्रदूषण के कारण न बन जाएँ। असम (ब्रह्म पुत्र),और दक्षिण की कुछ नदिया (जैसे कृष्णा-कावेरी) अभी प्रदूषण से कुछ बची हुई हैं. इनसे पूरे देश को सबक लेना चाहिए। कुल मिला कर जन जागरण अभियान चला कर हम नदियों को बचा सकते है, और नदियों के बहाने देश को बचा सकते हैं। इसके लिए हरियाली की चिंता करें। जंगल बचें। अब समय आ गया है की पूरा देश जल संरक्षण के मामले में बेहद गम्भीर हो जाए। जल नहीं तो कल नहीं, यह एक नारा नहीं, सच्चाई है. बहुत पहले कवि रहीम कह गए बिन पानी सब सून. अगर हम अभी नहीं चेते तो सब कुछ सून होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरा एक और मुक्तक है,

नदी को हम बचाएंगे, नदी हमको बचाएगी .
अगर प्यासे रहेंगे तो हमें पानी पिलाएगी .
नदी है माँ हमारी उसपे कोई आंच न आए,
अगर वो मिट गयी तो फिर हमे भी वो मिटाएगी.

राज्य के 326 हाजी आज सफर-ए-हज के लिए हुए रवाना

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया की, हज 2023 के लिए आज नागपुर के अंतरराष्ट्रीय विमानतल से फ्लायनास की फ्लाइट नंबर &4 5576 से राज्य के 326 हाजियों का पहला जत्था हज के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर विशेष रुप से खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन , जीव जंतु बोर्ड के अध्यक्ष विद्याभूषण शुक्ला, रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शिव सिंह ठाकुर ने उपस्थित होकर प्रदेश के हज यात्रियों को यात्रा की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान, हज कमेटी के कार्यपालन अधिकारी सचिव साजिद मेमन, सदस्य मौलाना कारी अशफाक अंजुम, मौलाना कारी इमरान अशरफी मोहम्मद इमरान, शमीम अख्तर उपस्थित रहे।

भाजपा ने की बीजेवायएम के सहप्रभारियों की नियुक्ति

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा ने बीजेवायएम के सहप्रभारी की नियुक्ति की है. युवा नेता सुशांत शुक्ला को नवीन दायित्व के तहत प्रदेश भाजयुमो का सह प्रभारी बनाया गया है. साथ ही वैभव बैस को सहप्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. युवा संगठन के कार्यों में कसावट लाने और अधिक सक्रिय करने के लिए बिलासपुर के इस युवा नेता सुशांत शुक्ला को ज़िम्मेदारी दी गई है. सह प्रभारी नियुक्ति के साथ वर्तमान दायित्व में मीडिया पेनलिस्ट, मीडिया विभाग भाजपा छत्तीसगढ़ और विधानसभा प्रभारी, चन्द्रपुर विधानसभा के प्रभारी भी हैं.इसके पहले भी लगातार कई वर्षों तक पूर्व राष्ट्रीय संयोजक एंव सदस्य-कार्यसमिति भारतीय जनता युवा मोर्चा के रुप में कार्य करते हुए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के प्रदेश प्रभारी की रूप अपने दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं.

मानसून से पहले भीषण गर्मी

रायपुर। समूचा छत्तीसगढ़ इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। जांजगीर का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। रायपुर, रायगढ़, मुंगेली सहित कई जिलों में चल रही है लू, लोगों का सुबह 11 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। दैनिक कामकाज भी प्रभावित होने लगा है और अब लोगों को बेसब्री से मानसून का इंतजार हो रहा है। संभावना जतायी जा रह है कि 20 जून के आसपास मानसून दस्तक दे सकती है। लेकिन इससे पहले तेज गर्मी ने परेशान कर रखा है। मौसम विभाग विभाग ने आने वाले 24 घंटे के लिए बस्तर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां लू चलने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा 48 घंटों के लिए 5 जिलों के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

15 साल के भ्रष्टाचार हमारे चुनावी हथियार होंगे : मरकाम

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार की उपलब्धियों और मोदी सरकार की नाकामियां तथा वायदा खिलाफी को जनता के बीच लेकर जायेंगे। साथ ही भाजपा की रमन सरकार के 15

साल के भ्रष्टाचार भी हमारे चुनावी हथियार पर होंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र के 95 प्रतिशत वायदों को पूरा किया है वहीं भाजपा की मोदी सरकार ने अपने महत्वपूर्ण वायदो 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार, किसानों की आय दुगुनी करने तथा 100 दिनों में महंगाई कर विदेश से कालाधन लाना तथा हर के खाते में 15 लाख जैसे वादो को मोदी सरकार ने जमुला बता दिया था। इसे भी हम जनता के बीच लेकर जायेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। संभागीय सम्मेलनों के बाद विधानसभा स्तर पर होने वाले सम्मेलनों से पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी नीतियों और योजनाओं का प्रशिक्षण देकर जनता के बीच भेजेगी। हमारी तैयारी बूथों तक पूरी हो चुकी है।आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार के काम और जनकल्याणकारी योजनायें कांग्रेस सरकार का ब्रह्मास्त्र होगी। भाजपा के पास कांग्रेस का मुकाबला करने के लिये कोई मुद्दा नहीं है।

नहीं होगी वोल्टेज की समस्या, बढ़ाई गई पारेषण क्षमता

रायपुर ।छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी निरंतर और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के लिए प्रदेश में लगातार पारेषण क्षमता का विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में आज 132/33 केवीए सब-स्टेशन बरमकेला में 40 मेगावोल्ट एंपीयर का तीसरा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। इससे वहां के 300 गांवों के उपभोक्ताओं को निर्बाध और बेहतर वोल्टेज के साथ बिजली मिल सकेगी। मुख्यमंत्रीभूपेश बघेल जी के निर्देश पर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विद्युत पारेषण प्रणाली को मजबूत करने विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले में स्थित 132/33 केवी उपकेन्द्र में एक अतिरिक्त 40 एमव्हीए (मेगा वोल्ट एम्पीयर) क्षमता की नयी ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। आज इसे सफलतापूर्वक ऊर्जीकृत किया गया। इससे बरमकेला सब-स्टेशन की क्षमता 120 एमवीए हो गई है। इसकी लागत चार करोड़ 88 लाख रुपए है। मानसून के पूर्व अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगने से क्षेत्र के हजारों किसानों को बेहतर बिजली मिल सकेगी। इस क्षेत्र मंत काफी संख्या में कृषि पंप हैं, साथ ही औद्योगिक इकाईयों और घरेलू उपभोक्ताओं को लगातार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इस अवसर पर मुख्य अभियंता श्रीमती कल्पना घाटे, अधीक्षण अभियंता सर्वश्री सीएम बाजपेयी, मनीष तनेजा, आरके अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता सर्वश्री जीआर जायसवाल, नरेंद्र नायिक, जेपी सिदार, मोहित बंजारे, एस. भास्करन, सहायक अभियंता मनोज पटेल, बजरंग विश्वकर्मा, मोहन पैकरा, एच. वारे, नीलिमा सिंह, आलोक साव उपस्थित थे।

कार्यकर्ताओं को मोदी चालीसा पढ़ाया जा रहा: धनंजय

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहां की भाजपा के टिफिन पॉलिटिक्स का भाजपा परिवार के गृहणीयो ने बढ़ती महंगाई के चलते बहिष्कार कर दिया। कार्यकर्ताओ ने बढ़ती महंगाई के चलते टिफिन लाने से इंकार कर महंगाई को नकारने वाले ओम माथुर जैसे मोदी

के चाटुकार नेताओ को आईना दिखाया है। भाजपा ने धरसींवा के कार्यकर्ताओं को टिफिन लेकर बैठक में बुलाया था विरोध के बाद रेस्टोरेंट में खाने की व्यवस्था कर ओम माथुर के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा नेताओं पर तंज कसा कहा कि भाजपा मोदी सरकार की 9 साल असफलता छिपाने कितनी भी रंग बिरंगी पुस्तक छपवा ले बड़े बड़े होर्डिंग लगवा ले 24 घण्टा टीवी में विज्ञापन चलवा ले सच्चाई पर पर्दा नही कर सकते देश की जनता मोदी निर्मित आपदा से पीड़ित है और भाजपा के कार्यकर्ता भी अछूते नही है। जिन कार्यकर्ताओ से दबावपूर्वक गुणगान करने मोदी चालीसा पढ़ाया जा रहा था वही कार्यकर्ताओं ने टिफिन लाने से इंकार कर महंगाई का विरोध किया है अब तो भाजपा के मोदीभक्त नेताओ को शर्म आना चाहिए और जनता की परेशानी समझना चाहिये।

रेल मंत्रालय भगवान भरोसे चल रही है : सुरेंद्र वर्मा

रायपुर। जयरामनगर के पास एक ही पटरी में आमने-सामने दो ट्रेनों के आने को रेलवे की लापरवाही करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद रेल मंत्रालय भगवान भरोसा चल रही है रेलवे में लगातार तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही है समय पर लोगों को ट्रेन नहीं मिलता है अचानक ट्रेन रद्द हो जाती है और कई बार तो ऐसा हुआ है कि जिस ट्रेन को उत्तर

प्रदेश जाना था वह ट्रेन उड़ीसा चली गई है ऐसे गंभीर लापरवाही सामने आ रही है।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि ओडिशा के बालेश्वर जिले में हुई भीषण रेल दुर्घटना और उसमें हुई हजारों की मौत और हजारों के घायल होने के बाद राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान हुआ है उससे रेल मंत्रालय में कोई सुधार नहीं हुआ है उस दुर्घटना से रेल मंत्रालय ने कोई सबक नहीं लिया है ऐसा लगता है कि रेल मंत्रालय ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है इसलिए लगातार इस प्रकार की लापरवाही हो रही है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जयराम नगर के पास एक ही पटरी पर एक ही समय में दो अलग-अलग दिशाओं से मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन का आना रेल मंत्रालय की लापरवाही को दर्शाता है ईश्वर की कृपा से कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया नहीं तो इस बात से इंकार नहीं कि उड़ीसा के बालेश्वर जिले में हुई घटना की तरह ही त्रासदी छत्तीसगढ़ में भी होती। भारतीय रेल रोज़ाना करीब 2.2 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाती है।

अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में अबकी बार 80 पार का नारा बुलंद

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी श्री निजामुद्दीन राइन जी एवं सह प्रभारी श्री आसिफ पाशा जी के प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष श्री अमीन मेमन जी की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक एवं कार्यकर्ता सम्मेलन दिनांक 12 जून रविवार दोपहर 2 बजे राजीव भवन रायपुर में आयोजित किया गया, जिसमे छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला जी एवं ओडिशा अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी अब्दुल कलाम जी भी मौजूद रहे.। प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने इस कार्यकारिणी में हिस्सा लिया.।सुबह से ही नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी निजामुद्दीन राइन एवं सह प्रभारी आसिफ पाशा जी के स्वागत का सिलसिला जारी रहा, एयरपोर्ट से लेकर राजीव भवन तक बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रभारियों का भव्य स्वागत किया.। बैठक की शुरुआत से पूर्व झीरम शहीदों को नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की।

कटंग बांस के रोपण समेत बांस उद्योग को बढ़ावा देने विशेष पहल

- किसानों को समृद्ध बनाने और पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से
- लगभग दो लाख एकड़ में बांस के रोपण से होगी कार्ययोजना की शुरूआत

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में कटंग बांस के रोपण सहित बांस उद्योग को बढ़ावा देने विशेष पहल हो रही है। इसके तहत वन विभाग द्वारा तैयार की जा रही कार्ययोजना अंतर्गत लगभग दो लाख एकड़ में कटंग बांस के रोपण से इसकी शुरूआत होगी।

मुख्यमंत्री श्री बघेल की अध्यक्षता में आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में वन विभाग द्वारा बांस रोपण और उपयोगिता के संबंध में विस्तार से प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ में बांस रोपण और इसके उद्योग के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में बांस रोपण और इसके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। यह कार्ययोजना किसानों को समृद्ध बनाने और मौसम परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने सहित पर्यावरण सुधार में महत्वपूर्ण साबित होगी।

बैठक में वन विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि बांस की खेती बहुत लाभदायक है। यह इमारती लकड़ी का एक बेहतर विकल्प भी है। मौजूदा समय में इसका व्यापक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। बांस उद्योग कई तरह के रोजगार सृजित करने में सहायक है। इसके रोपण पर प्राय एक ही बार खर्चा होता है और मौसम की मार से बेअसर होता है, इसलिए इसमें नुकसान की गुंजाइश न के बराबर होता है। यह जल संरक्षण और मृदा संरक्षण के लिए विशेष लाभकारी है। बांस का रोपण पर्यावरण के लिए लाभकारी, हरियाली बढ़ाने और तापमान संतुलन करने में भी सहायक है।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव द्वय शिशुपाल सोरी एवं चंद्रदेव राय, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा और वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्ही. श्रीनिवास राव तथा विभागीय अधिकारी आलोक तिवारी, दिलराज प्रभाकर, मयंक अग्रवाल तथा बांस उद्यमी श्री देबोपम मुखर्जी आदि उपस्थित थे।

राज्य सरकार खरीदती है किसानों का धान, ऋण लेकर करती है भुगतान

रायपुर। वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि धान खरीदी राज्य सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के पंजीकृत किसानों से धान खरीदी करती है और बैंको से ऋण लेकर भुगतान करती है। केन्द्र सरकार द्वारा धान खरीदी के लिए कोई अनुदान, सहायता अथवा ऋण नहीं दी जाती। धान खरीदी का एक सिस्टम है, राज्य सरकार किसानों से धान खरीदी करती है फिर कस्टम मिलिंग के बाद सेन्ट्रल पूल में चावल जमा किया जाता है। उसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा जमा चावल के एवज में निर्धारित दर पर भुगतान किया जाता है। वर्ष 2023-24 में 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। उन्होंने बताया कि किसानों से अब तक 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी की जा रही थी, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का निर्णय लिया है।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बारे में बताया कि धान खरीदी राज्य सरकार की सबसे बड़ी योजना है। धान खरीदी के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष 20 से 25 हजार करोड़ रूपए का ऋण लेती है। यह ऋण छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के माध्यम से बैंको एवं नाबार्ड इत्यादि से लिया जाता है। धान खरीदी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को कोई सहायता नहीं दी जाती और न ही कोई अनुदान या ऋण दिया जाता है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.